₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अगस्त 2025

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

संग्राम चुनाव का मुद्दा SIR

'वोटर अधिकार यात्रा' पर युवराज

CCL
Fuelling Sustainable Growth
79वें स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
भारत सरकार का एक उपक्रम/ कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी
दरभंगा हाउस, रांची - 834001 (झारखंड)

K.L.S. COLLEGE, NAWADA
805110 (Bihar)
A Constituent Unit of Magadh University, Bodhgaya, Bihar, India
**** Highlights of the College Facilities ****
Cultural and co-curricular activities.
12 Acre of large campus in town.
Well-developed library with rare books.
Well-developed Science and Commerce lab.
Fully Wi-Fi and Eco-friendly Campus.
Modernized Computer laboratories.
Smart classroom.
Open Gym facilities.
Separate common room for girls and boys.
24 hours CCTV surveillance.
Principal
Dr. Shailaj Kumar Shrivastava
Bursar
Dr. Rajeev Kumar
Technology Communication:
Communication Address:

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ।
METHODIST HOSPITAL
PRATAPSAGAR BUXAR
-: सुविधाएँ :-
सभी सुविधाओं से लैश।
मुफ्त रेलवे पास।
गरीब रोगियों को विशेष छूट।
प्रताप सागर,
बक्सर-802101 (बिहार)
डॉ0 आर.के. सिंह

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर
समस्त देशवासियों सहित पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों,
केवल सच के पाठकों और विज्ञापनदाताओं को
हार्दिक शुभकामनाएँ।
निवेदक :- श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

काजोल
05 अगस्त 1974

वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969

कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948

महेश बाबू
09 अगस्त 1975

सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961

सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952

स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963

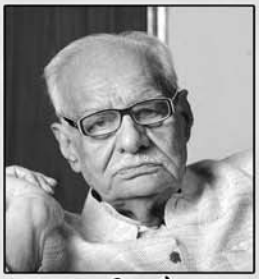

कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923

सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983

अदनान सामी
15 अगस्त 1973

अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968

सैफ अली खान
16 अगस्त 1970

दलेर मेंहदी
18 अगस्त 1967

स्व०राजीव गांधी
20 अगस्त 1944

रणदीप हुड्डा
20 अगस्त 1976

चिरंजिवी
22 अगस्त 1955

मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966

मेनका गांधी
26 अगस्त 1956

दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972

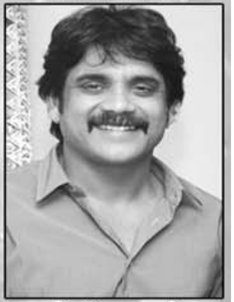

अक्केनी नार्गाजुन
29 अगस्त 1959

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha, A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

79वां आजादी का दिवस बड़े ही धूम-धाम से मनाया जायेगा और जिलेबी - मिठाई खाकर एकदिवसीय आजादी का पर्व को सम्पन्न कर लिया जायेगा। ***364*** दिन ***6*** घंटे आजादी के नाम पर कोई न कोई, किसी न किसी को गाली देता रहेगा। सोसल मीडिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से किसने, किसको गाली दिया यह चंद मिनटों में देश के आवाम को पता चल जाता है। कहने के लिए यहां भारत देश में चार धर्म है और अनेकों पंथ है जबकि सनातन के अनुसार एक ही धर्म है और बाकी सब पंथ है। हिन्दू ही हिन्दुत्व पर कालिख पोतने को तैयार बैठा है जिसकी वजह से साधु - संतों पर भी अपशब्दों का बौछार करने से गुरेज नहीं करते बल्कि भगवान को भी गाली देने से बाज नहीं आते। जिस संविधान की दुहाई देते हैं उस संविधान में भगवान को प्रतिष्ठा दिया जाता है उस भगवान को सोसल मीडिया पर अपमानित किया जाता है और आजादी के नाम पर उसपर ठोस कार्रवाई नहीं होती। संत प्रेमानंद और कथावाचक अनिरूद्धाचार्य के बयान पर कुछ फिल्मी कलाकार और कुछ महिला पत्रकार भी अपनी मर्यादा को लांघ कर गंदी बात कर रही है। प्रेमानंद महाराज और अनिरूद्धाचार्य ने चार जगहों पर मुंह मारने वाली लड़कियों एवं महिलाओं से बचने की सलाह दी तो उनकी गंदी आत्मा बौखला गयी और संतो पर भी प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। धर्म पर प्रहार करने वाली शिक्षित एवं दूषित महिलाएं को उचित स्थान बताने वाले संतो को सनातन प्रेमी उनकी वाणी का समर्थन कर रहे हैं।

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक

8340360961, 9431073769

गाली देने की है आजादी

आजादी के 79 वर्ष में हमारा भारत काफी विकसित हुआ है और इसके तेज गति से दूसरे देश के लोगों को इसकी बढ़ती साख से जलन हो रहा है। भारत में लगतार विपक्ष में रहने की वजह से कांग्रेस एवं उनके गठबंधन के पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सभी कार्य गड़बड़ लगते हैं जिसकी वजह से पीएम को तुम-तबड़ाक करने से भी बाज नहीं आते। भारत देश बंटवारे के बाद हिन्दू प्रधान देश के रूप में खास स्थान रखता है लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए सनातन धर्म को वायरस की उपाधि दी जाती है और उनके समर्थक हिन्दू होकर भी गाली देने से बाज नहीं आते। आजादी का मतलब था चहुमुंखी विकास जिससे आम से खास तक समृद्ध बनकर अपनी शक्ति का परिचय करा सकें। संविधान की दुहाई देने वाले राजनेता और उनके समर्थक किस प्रकार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं यह देश की आवाम देख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सनातन धर्म प्रति आस्था ने देश के भीतर हिन्दूवादी शक्ति को एकत्रित कर दिया है। आज वर्त्तमान समय में कथावाचकों ने देश की भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ देश की एकता को खंडित करने वाले फिल्मी कलाकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। आजादी की परिभाषा को 21वीं सदी में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन आजादी में बहते खून की महत्ता को बरकरार रखने वाले विरोधियों का सामना काने को तैयार हैं। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरूद्धाचार्य जी महाराज ने अभद्र महिलाओं पर सख्त टिप्पणी की तो भारत देश में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को ऐसा लगा कि उनको संतों एवं पीएम मोदी को घेरने का अवसर मिल गया है लेकिन जिस प्रकार भारतीय महिलाओं एवं बेटियों ने खुलकर संतों के पक्ष में गोलबंद होकर आवाज बुलंद किया उससे विरोधी स्वर चारों खाने चित हो गयी। भारत में एक कहावत है **''लोहा-लोहे को काटता है''**, उसी के तर्ज पर भारत के चर्चित संत श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने संत प्रेमानंद महाराज पर प्रहार कर अपनी बढ़ती लोकप्रियता पर ग्रहण लगाने का काम किया है। श्री रामभद्राचार्य एवं श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पहचान भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में की है और यही कारण है यह लोग शंकराचार्य पर भी प्रहार करने से बाज नहीं आते। शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती के विद्वता पर उंगली उठाना राजनीति से प्रेरित लगता है। लोकतंत्र का चारो स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं पत्रकारिता भी आजादी के नाम पर गाली-गलौज करने से बाज नहीं आते और यही वजह है की देश की जनता को अब किसी भी स्तंभ पर भरोसा नहीं बचा है। **पत्रकार चित्रा त्रिपाठी** का भी चेहरा उजागर हो चुका है और इनकी लेखनी और बयान की वजह से आवाम के बीच काफी थू-थू हो रहा है। सोसल मीडिया पर कब किसको गाली-गलौज कर देगा कहना मुश्किल है। देश की सेना पर उंगली उठाना और उसके **सर्जिकल स्ट्राइक** के साथ-साथ **ऑपरेशन सिन्दूर** की ठोस कार्रवाई पर अभद्र टिप्पणी करना आदत बन चुका है। सोनागाछी की सेक्स वर्करों ने भी कहा कि है हम से भी ज्यादा कुसूरवार फिल्मी कलाकारों का है क्योंकि उनकी हरकते मर्यादा को लांघती जा रही हैं और घर-घर की बेटियों को बर्बाद कर रही है। वेश्याएं बंद कमरे में अपने जीवन के लिए देह बेच रही हैं परन्तु फिल्म से जुड़ी महिलाएं जिस प्रकार नंगापन का परिचय दे रही हैं और संतों पर प्रहार कर रही हैं। आजादी के नाम पर ब्राह्म्णों एवं राजपूतों को गाली देना आम बात हो गया है और बार-बार ब्राह्म्णों को विदेशी कहकर अपमानित किया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई भी नेता एवं विभिन्न जाति के लोग संविधान का हवाला देकर कुछ भी बोल जाते हैं और अगर यही बात सवर्ण कह दें तो उनपर एससी/एसटी एक्ट का दंड भुगतना पड़ता है। बिहार में चुनाव का समय है इसलिए सभी पार्टियां अपने पार्टी को विजयी बनाने के लिए जिससे नुकसान हो सकता है उसको गाली देने से परहेज नहीं करती क्योंकि 1947 में मिली आजादी का यही मूलमंत्र बनता जा रहा है।

जुलाई 2025

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

हमारा पता है :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड् नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

महुआ को रौशन

ब्रजेश जी,

मैं केवल सच पत्रिका का नियमित पाठक हूँ और इसकी सभी खबरों को पढ़ता हूं. सोनू यादव ने जुलाई अंक 2025 में अपनी खबर महुआ को रौशन कर रहे हैं डॉ मुकेश कुमार रौशन के बढ़ते वजूद पर कारगर ढंग से सच्चाई को रखा है. महुआ विधानसभा से तेजप्रताप चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं जबकि राजद के छात्र युवा संसद कार्यक्रम में मुकेश रौशन की जलवा ने साबित कर दिया है कि अपने विधानसभा का विकास किया है। अच्छी खबर है.

✦ संजय सिन्हा, रामआशीष चौक, हाजीपुर

2027 की तैयारी

ब्रजेश जी,

केवल सच पत्रिका के जुलाई 2025 में पत्रकार अजय कुमार ने उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के विषय में खबर को पाठकों को बीच रखा है. केशव मौर्य के सहारे भाजपा का ओबीसी दांव खबर में संगठन और सत्ता के संतुलन से 2027 की तैयारी किस प्रकार की जा रही है और कैसे सत्ता को नियमित भाजपा करेगी उसकी तैयारी अभी से हो रहा है पढ़कर सही जानकारी मिली. योगी की सख्ती से यूपी के दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स वहां काम नहीं करना चाहते हैं. धारदार खबर लगा.

✦राजीव रंजन मिश्र, अशोक नगर, नई दिल्ली

अन्दर के पन्नों में

इंसाफ की जिद् पर अड़ा परिवार.......58

सरदार

मिश्रा जी,

आपका संपादकीय सरल भाषा में लिखे जाने की वजह से पाठकों को सटीक जानकारी मिलती है. जुलाई अंक 2025 में बिहार का कौन होगा सरदार संपादकीय में अपने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को बहुत कारगर ढंग से आवाम को बताया है कि कौन होगा सरदार. विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी रहेगी और बिहार की जनता किस दल पर भरोसा करती है स्पष्ट बताने की सार्थक कोशिश की है और जातिवाद का कितना महत्व रहेगा उस विषय पर भी आपका आलेख लोगों का ध्यान अपनी और खींचता है. काफी अच्छा संग्रह है इस अंक में.

✦ रंजीत राय, रमना रोड, गया बिहार

सिलसिला

मिश्रा जी,

बिहार प्रदेश में विगत कुछ महीनों में अपराधियों ने सरकार और बिहार पुलिस की नींद हराम कर दिया. विकास के साथ साथ हत्याओं की गति भी बढ़ती रही, जिसकी वजह से जंगलराज जैसा माहौल बना रहा और बिहार पुलिस का यह बयान की तीन महीने में आपराधिक वारदात होता है, इस प्रकार के बयान से विपक्ष एवं प्रदेशवासी भी हतप्रद हैं. राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा है कि चुनाव कितना भयमुक्त होगा. पत्रकार अमित कुमार ने जुलाई 2025 अंक में सटीक एवं चिंताजनक खबर को लिखा है. खबर बड़ा है पर पठनीय है.

✦ महेश कुमार वर्मा, टावर चौक मुंगेर, बिहार

कानूनी सलाह

संपादक जी,

जुलाई अंक 2025 अंक में केवल सच, पत्रिका के स्थापना वर्ष के अवसर पर हुए कार्यक्रम की खबर पढ़कर बहुत अच्छा लगा. शून्य से शिखर तक विशेषांक का विमोचन और आर्यभट्ट केवल सच सम्मान 2025 से विभिन्न क्षेत्र के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया. इस प्रकार के कार्यक्रम करके पत्रिका प्रबंध न समाज में मजबूत संदेश दे रहा है. हजारों लोगों की उपस्थिति रही जिसका मैं भी गवाह बना. यह अंक सच में काबिले तारीफ है. केवल सच सोसल साइट पर भी मजबूती से अपना स्थान बनाता जा रहा है.

✦ प्रमोद मुखर्जी, बाबू बाजार, कोलकात्ता पंबं

झारखंड

संपादक जी,

केवल सच पत्रिका के जुलाई 2025 अंक में पत्रकार गुड्डी साव और ओम प्रकाश ने राजनीति एवं अपराध से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है. छोटी छोटी खबरों को स्थान देना सही है. झारखंड सरकार के विभाग में फैले भ्रष्टाचार की मजबूत खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित करना चाहिए. जमीन हड़पने के कई मामले आ रहे है कि सरकार के मंत्री विधायक की भूमिका संदिग्ध है उसपर भी दमदार खबर आना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिल सके. इसलिए आपकी जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है. सभी खबरें पठनीय है.

✦ अभिषेक राय, 104, हाउसिंग कॉलोनी, राँची

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्षः- 20	अंकः- 231	माहः- अगस्त 2025	मूल्यः- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानंद राय 9905250798

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

पंकज कुमार सिंह 9693850669, 9430605967

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

अविनाश कुमार 7992258137, 9430985773

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

ऋषिकेश पाण्डेय 7488141563, 7323850870

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०) :-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०) :-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०) :-	मुकेश कुमार	9473038020
बाढ़ :-		
भोजपुर :-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर :-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर :-		
रोहतास :-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
:-		
गया (श०) :-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०) :-		
औरंगाबाद :-		
जहानाबाद :-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल :-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा :-		
:-		
नवादा :-	अमित कुमार	9162664468
:-		
मुंगेर :-		
लखीसराय :-		
शेखपुरा :-		
बेगूसराय :-		
:-		
खगड़िया :-		
समस्तीपुर :-		
जमुई :-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली :-		
:-		
छपरा :-		
सिवान :-		
:-		
गोपालगंज :-		
:-		
मुजफ्फरपुर :- .		
:-		
सीतामढ़ी :-		
शिवहर :-		
बेतिया :-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा :-		
मोतिहारी :-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा :-		
:-		
मधुबनी :-		
:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा :-		
मधेपुरा :-		
सुपौल :-		
किशनगंज :-		
:-		
अररिया :-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया :-		
कटिहार :-		
भागलपुर, :-		
(ग्रा०) :-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया :-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
................................., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय त्तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
................................., स्टेट हेड
सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

....

....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप	7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र	7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव	9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

....

संयुक्त संपादक

....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

....

....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:-	
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं " केवल सच टाइम्स "**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

महेश चौधरी	9572600789, 9939419319
आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
शालनी झा	9031374771, 7992437667
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
कुमार राजू	9310173983
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो

राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाईबासा		

'वोटर अधिकार यात्रा' पर युवराज संग्राम चुनाव का मुद्दा SIR

● अमित कुमार

राजनीतिक लड़ाई के अपने-अपने अंदाज होते हैं। कोई नीतियों की पटरी पर राजनीतिक गाड़ी दौड़ाता है तो कोई धर्म के नाम पर राजनीति की ऊंचाई तक पहुंचता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति का अस्त्र ग्रामीण ठेठ भाषा को बना लिया। वह भी गंवई अंदाज में जहां भप्प, चुप जैसे शब्द चलते हैं और ग्रामीण मुहावरा उनका अस्त्र। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ग्रामीण अंदाज का सिक्का खूब चलाया। अब एक खास अंतराल के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सक्रिय राजनीति का साफा बांध लिया है। इस बार की जंग में एक अंतर है। वह यह कि इस बार का चुनावी जंग अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक ले जाने की है। बता दें कि बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' के पहले संबोधन से राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने गंवई अंदाज को परोसते दलित, पीड़ित और सेक्युलर जनता में उत्साह भर गए। राजद नेतृत्व को चाहने वाली भीड़ लालू यादव के एक लटके झटके से ही झूमने लगे। राजद सुप्रीमो ने बस एक नारा दिया लोकतंत्र को बचाना है, भाजपा को भगाना है। इसके साथ राजद सुप्रीमो ने 'लागल-लागल झुलनियां में धक्का, बलम कलकत्ता चलअ...' का तड़का क्या लगाया पूरी जनसभा में उत्साह भर गए। राहुल गांधी के चेहरे में भी रौनक आया। बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खरगे

लालू प्रसाद यादव

और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हंसने लगे। राजनीतिक सभाओं में यूं ही नहीं बोलते लालू यादव। वोट अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव एक मिनट ही बोले होंगे पर सासाराम की दलित, पिछड़ी और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही पूरी आक्रामकता के साथ बोल गए। लालू यादव को पता है कि यह वह क्षेत्र है जहां लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन ने 100 फीसदी रिजल्ट देते सासाराम, बक्सर, आरा और काराकाट लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लिया। इस बार लालू यादव के निशाने पर शाहाबाद की 22 विधानसभा सीटें हैं। गत् चुनाव में एनडीए को मात्र दो सीटों पर ही जीत मिली थी। बाकी 20 सीटों पर महागठबंधन ने जीत का परचम लहराया था। सासाराम में लालू यादव ने अपने संबोधन से महागठबंधन की राजनीत को अपनी सक्रियता से भरपूर ताकत और दलित पीड़ित को भरोसा तो दे ही दिया। बहरहाल, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत देश में मौजूदा हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। यादव ने कहा कि

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान हर मतदाता को मतदान का अधिकार देता है। भाजपा और उसके सहयोगी इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है कि इस यात्रा में हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सासाराम से शुरू होकर 1300 किलोमीटर लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार के 20 जिलों से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के लिए सासाराम रवाना होने से पहले ये बात कही। यात्रा रोहतास जिले से शुरू हो रही है। बेटे तेजस्वी यादव के साथ प्रसाद ने कहा, हम देश में मौजूदा हालात के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपातकाल से भी बदतर है। यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी भी हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव अब से बमुश्किल तीन महीने दूर हैं, ऐसे में राहुल गांधी, यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ सासाराम के बियाडा (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण) मैदान से यात्रा शुरू करेंगे। इसका समापन 16 दिनों के बाद एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। संविधान हर मतदाता को मतदान का अधिकार देता है। भाजपा और उसके सहयोगी इस अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है कि

इस यात्रा में हमें बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।

गौरतलब है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' कर रहे हैं, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 'इंडिया' गठबंधन के कई अन्य नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की इस यात्रा में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को उठाया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में 16 दिन में 20 जिलों में कुल 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार–'एक व्यक्ति, एक वोट' की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा के डबल इंजन का एक डिब्बा नहीं बनाने दिया जा सकता। खेड़ा ने कहा, आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसलिए संभव है, क्योंकि हमारे पास वोट करने की ताकत है। राहुल गांधी जी ने संघर्ष शुरु किया है, ताकि देश में हर एक नागरिक आजादी से सांस ले सके। उन्होंने कहा, हमारे 'इंडिया' गठबंधन के साथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपील की, तो उच्चतम न्यायालय को भी इसमें दखल देना पड़ा। यह षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था। ये आपकी, हमारी पहचान छीनने का षड्यंत्र था। खेड़ा ने दावा किया कि आज दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, कल उनकी भागीदारी छीनी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, चुनाव आयोग इस 'डबल इंजन' का एक डब्बा बनकर रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं होगा। हम इसे लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार के लोगों से हम आग्रह करते हैं कि यह आपके अधिकार और हक की यात्रा है। आप भी इस यात्रा में शामिल हों, ताकि बिहार से लोकतंत्र को दिशा मिल सके। उन्होंने कहा, 'वोटर अधिकार यात्रा' एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। हम सबके अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये यात्रा एक मील का पत्थर

साबित होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ यह यात्रा कर रहे हैं। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की गई और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में 'इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी।

वही दूसरी तरफ पार्टी से छः साल के लिए निष्काषित किये जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी पार्टी के साथ खुद की पार्टी टीम तेजप्रताप यादव का गठबंधन किया। इसके बाद से ही वह राजद विरोधी बयान देते नजर आ रहे है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को असरहीन करार दिया है। उनका कहना है कि असली मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी हैं, जबकि यह यात्रा लोगों को भटकाने का काम कर रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए मुद्दों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने वाला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें क्योंकि इनसे केवल विपक्ष को राजनीतिक लाभ मिलता है। राजनीति में अक्सर बयानबाजी चर्चा का केंद्र बनती है। इस बार सुर्खियों में तेज प्रताप यादव हैं। एक निजी यूट्यूब चैनल से बातचीत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, एकदम है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है मेरे मन में। जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी पिताजी की तरह काम कर पाएंगे। तेज प्रताप का कहना है कि जब तक वे मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक अपने पिता लालू प्रसाद यादव जैसा काम नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि लालू ने जमीन से जुड़े रहकर लोगों की सेवा की थी, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में यह कमी दिखती है। "मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसके मन में नहीं होती? क्रिकेट खेल रहा है तो कप्तान बनने का मन करता है, स्कूल में पढ़ रहा है तो मॉनिटर बनने का मन करता है। ऐसे ही मेरे मन में भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है।

जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक पिताजी की तरह जनता की सेवा करना संभव नहीं होगा।" तेज प्रताप यादव ने इस बयान के साथ अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी इस काबिल नहीं हैं कि वे मुख्यमंत्री बनें। उनका आरोप है कि तेजस्वी असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे और गलत दिशा में जा रहे हैं। "हम तेजस्वी जी के लिए कहते थे पर अब वो उस लाइन पर नहीं जा रहे हैं। उनका लाइन धीरे-धीरे भटक रहा है। वे मुख्य मुद्दों से दूर होकर राहुल गांधी जैसे नेताओं के साथ नौटंकी में समय बर्बाद कर रहे हैं।" तेज प्रताप यादव ने न केवल तेजस्वी बल्कि राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी सिर्फ नौटंकी कर रही है। इससे बिहार की असली समस्याएं पीछे छूट रही हैं। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' जैसी बड़ी राजनीतिक गतिविधि शुरू की है। तेज प्रताप का यह बयान उस रणनीति पर भी सवाल खड़ा करता है। बता दें कि तेज प्रताप यादव की छवि अब तक ज्यादा विवादित बयानों और व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर चर्चा में रही है। वे 2015 में पहली बार विधायक बने और मंत्री भी रहे, लेकिन कई बार अजीबोगरीब बयान, धार्मिक और पौराणिक रूपकों के जरिए राजनीति करने के कारण वे मजाक का विषय बने। इसके बावजूद, वे लगातार खुद को एक गंभीर नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। उनका यह बयान उनके राजनीतिक करियर की दिशा तय करने में अहम मोड़ साबित हो सकता है। तेज प्रताप यादव का "मुख्यमंत्री बनने की इच्छा" वाला बयान न केवल उनके भविष्य की राजनीति की दिशा दिखाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि राजद परिवार में अंदरूनी मतभेद गहराते जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी इस लायक नहीं हैं और राहुल गांधी के साथ मिलकर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी ने सासाराम से 1,300 किमी लंबी 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की है।

विदित हो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए चुनाव में वोट चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ने का फिर से हवाला दिया और दावा किया कि सारे नए मतदाताओं के वोट भाजपा को मिले। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने जादू से लाखों मतदाता पैदा किए। राहुल गांधी

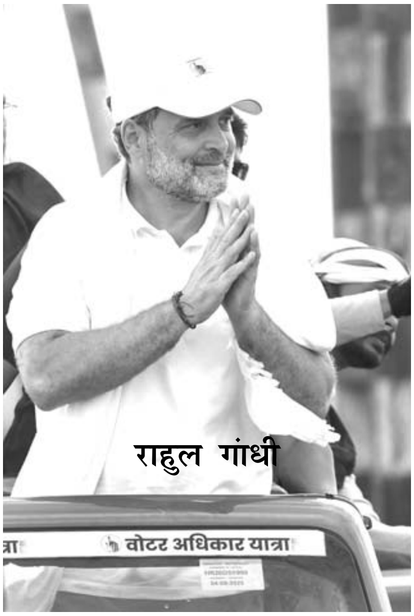

राहुल गांधी

ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात तो कर दी, लेकिन यह पता है कि वह असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत से पहले आयोजित सभा में यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि पूरे देश में वोट की चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ने का फिर से हवाला दिया और दावा किया कि सारे नए मतदाताओं के वोट भाजपा को मिले। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर मतदाता सूची के बारे में जानकारी एकत्र की गई। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़कर और नाम हटाकर चुनाव की चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, जहां भी वोट की चोरी हो रही है, वहां हम यह चोरी पकड़कर जनता को बताएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात तो कर दी, लेकिन यह पता है कि वह असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए। वही बता दें कि बिहार में मृत मतदाता का मसला

चर्चा के साथ के साथ विवाद में भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर भी अब जमकर वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए लिखा, 'जीवन में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका कभी नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए, चुनाव आयोग का धन्यवाद!'

दरअसल, बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 'मृत' घोषित मतदाताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की और चाय पी। इसके बाद चुनाव आयोग और वोटिंग अधिकारों पर चल रहे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुनवाई के बीच, राहुल गांधी ने उन सात मतदाताओं से मुलाकात की, जिन्हें चुनाव आयोग ने 'मृत' घोषित कर दिया था, लेकिन वे सभी जीवित हैं। दिलचस्प है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने का 'आकस्मिक तरीका' बताया है और इसे चुनाव आयोग की शक्तियों और एक आम नागरिक के वोट देने के अधिकार के बीच की लड़ाई करार दिया है। सनद् रहे कि राहुल गांधी ने राघोपुर में बिहार के इन सात मतदाताओं के साथ चाय पर चर्चा की। ये सभी मतदाता तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र से हैं। इन मतदाताओं ने राहुल गांधी को बताया कि वे अपने मताधिकार को वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को गंभीर राजनीतिक रंग देते हुए एक बयान जारी किया है। पार्टी ने कहा कि यह सिर्फ लिपिकीय त्रुटि नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक मताधिकार से वंचित करना है। कांग्रेस ने आगे आरोप लगाया, जब जीवित लोगों को मृत बताकर हटा दिया जाता है तो लोकतंत्र को ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस घटना ने बिहार चुनाव और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चल रहे विवाद को और गहरा कर दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले की कानूनी वैधता की जांच कर रहा है, वहीं राहुल गांधी की यह प्रतीकात्मक मुलाकात ने इसे एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। विपक्षी दल इस मामले को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमा सकता है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निर्वाचन आयोग 'वोट चोरी' में शामिल है और वह यह सब भाजपा के लिए कर रहा है। राहुल ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। मैं 100% सबूतों के साथ ये बात कह रहा हूं। हम जैसे ही ये सबूत सबके सामने रखेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संदेह था। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तरफ से जांच करवाई। इस जांच में 6 महीने लगे और जो हमें मिला है-वो एटम बम है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम

छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हों, चाहे आप रिटायर ही क्यों न हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं कि निर्वाचन आयोग में जो भी यह काम कर रहे हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह राष्ट्रदोह है। आप सेवानिवृत्त हो गए हों, या कहीं भी हों, आपको ढूंढ़कर निकालेंगे। वही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार देकर सभी लोगों को ताकत दिया, लेकिन भाजपा के लोग चुनाव आयोग को आगे करके वोट का अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, आपके (जनता) वोट की

चोरी नहीं, डकैती की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी बिहार को चूना लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी, यह बिहार है, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, बिहार में हम बेईमानी नहीं होने देंगे। राजद नेता ने दावा किया कि वह जिन वादों की घोषणा करते हैं, बिहार की नीतीश कुमार सरकार नकल करके वही घोषणाएं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में नकलची सरकार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमें मौका मिला तो हम बिहार में विकास करने वाली सरकार देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही यात्रा में वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएआईआर) के मुद्दे को उठाया जाएगा।

दिगर बात है कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभों में से एक चुनाव आयोग इन दिनों विपक्षी दलों के हमलों के केंद्र में है। और इस बार हमला न केवल तीखा है बल्कि ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्हें लंबे समय तक सत्ताधारी दल ने अपरिपक्व नेता की छवि में बांधने की कोशिश की, अब खुले मंचों से चुनाव आयोग को 'मर चुकी संस्था' कह रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर यह हमला साधारण नहीं। यह एक ऐसा बयान है जो संविधान, व्यवस्था और जनविश्वास तीनों को चुनौती देता है। यह बहस केवल एक व्यक्ति बनाम संस्था नहीं, बल्कि लोकतंत्र बनाम सत्ता-केन्द्रित राष्ट्रवाद के संघर्ष की नई कथा है। बीते 10 दिनों में तीसरी बार, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसा हमला बोला है, जिससे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की निष्पक्षता पर बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने बीते कुछ हफ्तों में कई बार चुनाव आयोग पर हमला बोला है, जिससे भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता पर बहस तेज हो गई है। 2 अगस्त, 2025 को विज्ञान भवन में दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है। अगर 10-15 सीटों पर

धांधली न होती, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। यह बयान सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की विश्वसीयता वैधता को चुनौती देता है। इस वाक्य ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील नस को छू लिया है-चुनाव प्रणाली और उसकी निष्पक्षता को। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 100 सीट पर धांधली हुई है और अगर इनमें से 15 सीट पर भी धांधली नहीं हुई होती, तो नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन में इस बात को फिर से दोहराया कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के जो सबूत मिले हैं, वो एटम बम की तरह हैं। उन्होंने कहा, हम अगले कुछ दिन में यह साबित करने जा रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और कैसे की गई। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इसका सबूत दिया जाएगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। उनके नए दावे पर निर्वाचन आयोग की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बहुत ही साधारण बहुमत के साथ हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 100 सीट पर धांधली हुई है और अगर इनमें से 15 सीट पर भी धांधली नहीं हुई होती, तो नरेन्द्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन में इस बात को फिर से दोहराया कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के जो सबूत मिले हैं, वो एटम बम की तरह हैं। उन्होंने कहा, हम अगले कुछ दिन में यह साबित करने जा रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और कैसे की गई। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इसका सबूत दिया जाएगा कि कैसे लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। उनके नए दावे पर निर्वाचन आयोग की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कहा

कि हमारा मानना है कि लोकसभा चुनाव में 70, 80 या 100 सीट तक पर धांधली हुई है। यदि 15 सीट पर भी धांधली नहीं हुई होती, तो वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। उन्होंने कहा, हम अगले कुछ दिन में यह साबित करने जा रहे हैं कि एक लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और कैसे की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 2014 से ही मुझे चुनाव प्रणाली पर संदेह है। भाजपा की प्रचंड जीत हासिल करने की क्षमता आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र में जो हुआ, उसने मुझे इस मुद्दे को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं बिना सबूत के कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने कहा कि इन सबूत के आधार पर देश को दिखा दिया जाएगा कि निर्वाचन आयोग की संस्था उस तरह काम नहीं करती, जैसा उसे करना चाहिए तथा यह समझौते का शिकार हो चुकी है। कांग्रेस के शीर्ष नेता ने दावा किया था कि निर्वाचन आयोग 'वोट चोरी' में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसा पुख्ता सबूत है, जो 'एटम बम' की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को निराधार और निंदनीय करार दिया तथा कहा कि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं आग से खेल रहा हूं और मैंने कहा कि मुझे पता है कि मैं आग से खेल रहा हूं और मैं आग से खेलना जारी रखूंगा। उन्होंने कहा आखिरकार, आप में से अधिकतर लोगों की तरह, मैं भी आग में विलीन हो जाऊंगा। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि कायरों से नहीं डरना चाहिए। सबसे कायरतापूर्ण काम जो आप कर सकते हैं, वह है किसी कायर से डरना। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा काफी हद तक कायरता पर

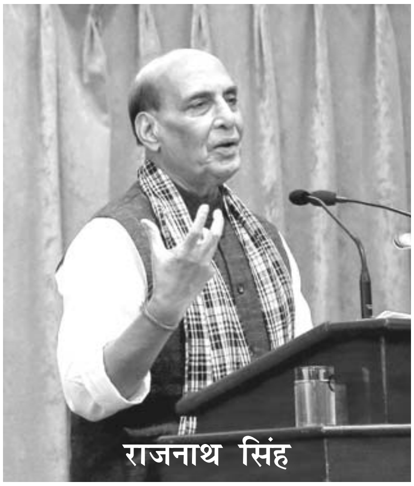
राजनाथ सिंह

आधारित है। राहुल गांधी ने इस बात का उल्लेख किया, जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, तो पाते हैं कि उस समय कई वकील सबसे आगे थे। वकील कांग्रेस पार्टी की रीढ़ हैं और आप ही वो लोग हैं, जिन्होंने संविधान की कल्पना की थी और इसके निर्माता थे।

बताते चले कि 1 अगस्त को राहुल गांधी ने जो बयान दिया वह समाचार चैनलों की हेडलाइन बन गया-'हमारे पास एटम बम है'। जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। इस राजनीतिक धमाके का जवाब दिया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने, जो खुद एक अनुभवी नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास परमाणु बम है तो उसे फोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आप सुरक्षित रहें। यह संवाद जितना तीखा था, उतना ही प्रतीकात्मक भी, यह सिर्फ आरोप- प्रत्यारोप नहीं बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही और साख पर सीधी बहस थी। यह संवाद दर्शाता है कि भारत में चुनाव अब केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक युद्ध का रूप ले चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने राहुल को निर्वाचन आयोग के खिलाफ 'सबूतों का एटम बम' फोड़ने की चुनौती दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में 'वोट चोरी' में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसा पुख्ता सबूत है, जो 'एटम बम' की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। पटना में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना एक चौराहे से की, जिसमें एक रास्ता आगे की प्रगति की ओर ले जाता है और दूसरा बिहार को अराजकता और जाति संघर्ष के पुराने दौर में वापस ले जाता है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है। अगर ऐसा है, तो उन्हें तुरंत उसे फोड़ देना चाहिए। उन्हें बस यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह खुद खतरे से दूर रहें। सिंह ने कहा कि देश को राहुल गांधी के पिछले बयानों की याद है। उन्होंने संसद में भूकंप आने की धमकी दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो वह एक बेकार बात साबित हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है, जो निर्विवाद ईमानदारी के लिए सम्मानित है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। विपक्ष के नेता को किसी संवैधानिक संस्था के बारे में निम्न स्तर की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। सिंह ने कांग्रेस नेता को याद दिलाया कि उनकी अपनी पार्टी के हाथ खून से रंगे हैं, जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी।

विदित हो कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उसकी अक्षमता और स्पष्ट पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। यह बयान उस समय आया जब मुख्य निर्वाचन

जयराम नरेश

आयुक्त ने बिहार में एसआईआर का बचाव किया और विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी कमियों को दूर करना होता है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और निर्वाचन आयोग के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। सीईसी की टिप्पणी के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया क्या आयोग उच्चतम न्यायालय के 14 अगस्त के आदेशों को अक्षरशः लागू करेगा। उन्होंने कहा कि आज, राहुल गांधी द्वारा सासाराम से 'इंडिया' गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने के कुछ ही देर बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने यह कहना शुरू किया कि वे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करते। रमेश ने 'एक्स' पर लिखा कि सच यह है कि तमाम विरोधाभासी सबूतों के बीच यह बेहद हास्यास्पद है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के किसी भी स्पष्ट सवाल का

सारगर्भित जवाब नहीं दिया। रमेश ने दावा किया कि गांधी ने अब तक जो कुछ भी कहा है वह निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर ही आधारित है। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग की न केवल अक्षमता बल्कि घोर पक्षपातपूर्ण नीति भी बेनकाब हो गई है। रमेश ने कहा, क्या निर्वाचन आयोग बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उच्चतम न्यायालय के 14 अगस्त, 2025 के आदेशों को अक्षरशः लागू करेगा? कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा, वह संवैधानिक रूप से ऐसा करने को बाध्य है। देश इंतजार कर रहा है और देख रहा है। एक अन्य पोस्ट में रमेश ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरल सलाह है कि जांच करें, डराएं नहीं। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब यह 'नया' निर्वाचन आयोग सीधे तौर पर बोल रहा था और सूत्रों के जरिए कोई जानकारी नहीं दे रहा था। रमेश ने कहा कि कल, निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों पर डालना था। उन्होंने कहा कि इस प्रेस नोट की विपक्षी दलों और आम जनता की ओर से भी तीखी आलोचना हुई थी। रमेश ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन भी बिहार एसआईआर के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नामों के प्रकाशन को रोकने के लिए चुनाव आयोग की हर दलील को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के तीन दिन बाद हुआ है। रमेश ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तीखी और दस्तावेजी आपत्तियों के बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने इन 65 लाख मतदाताओं के सभी विवरण खोजे जा सकने योग्य प्रारूप में प्रकाशित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता की पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड के इस्तेमाल की भी अनुमति दी थी। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर

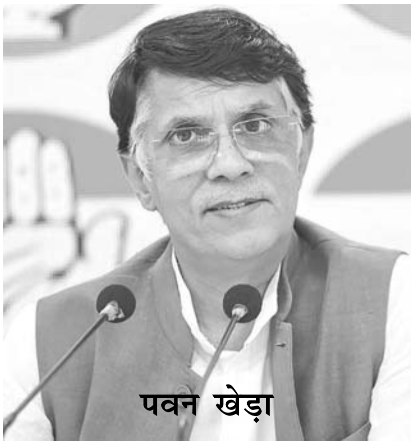

पवन खेड़ा

निशाना साधते हुए कहा कि आज जब ज्ञानेश कुमार सामने आए तो देश को पता चला कि वह ही मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लोग किसी "सूत्र" नामक व्यक्ति को ही मुख्य चुनाव आयुक्त समझते थे। खेड़ा ने 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो स्क्रिप्ट पढ़ी, वह भाजपा की थी। उन्होंने हाल के दिनों में कांग्रेस और राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।" उन्होंने कहा, "हम आपसे आपकी जिम्मेदारी समझने का आग्रह करते हैं... लोकतंत्र की हत्या की भाजपा की योजना का हिस्सा न बनें। कृपया संवाददाता सम्मेलन के दौरान किसी धारावाहिक की घटिया स्क्रिप्ट न पढ़ें, बल्कि पूछे गए सभी सवालों के जवाब दें।" इससे पहले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा था कि कुछ दल "गलत सूचना फैला रहे हैं और आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं।" सीईसी ने दोहरे मतदान और "वोट चोरी" के आरोपों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सभी हितधारक एसआईआर को पारदर्शी तरीके से सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) में शामिल दलों ने कथित "वोट चोरी" के खिलाफ बिहार में "मतदाता अधिकार यात्रा" शुरू की है।

वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगियों की लोगों को मताधिकार से वंचित करने की नापाक साजिश का पर्दाफाश करता है। तेजस्वी ने इस आदेश को संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जारी लड़ाई, विपक्षी दलों की एकता एवं संघर्ष और बिहार की जनता की एकजुटता की जीत करार दिया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर शीर्ष अदालत के आज के अंतरिम आदेश ने भाजपा, उसके सहयोगियों की लोगों को मताधिकार से वंचित करने की नापाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर नजर रखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे और साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के निर्वाचन आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। तेजस्वी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने संसद, विधानसभा, विधान परिषद और सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एसआईआर के संबंध में न्याय के

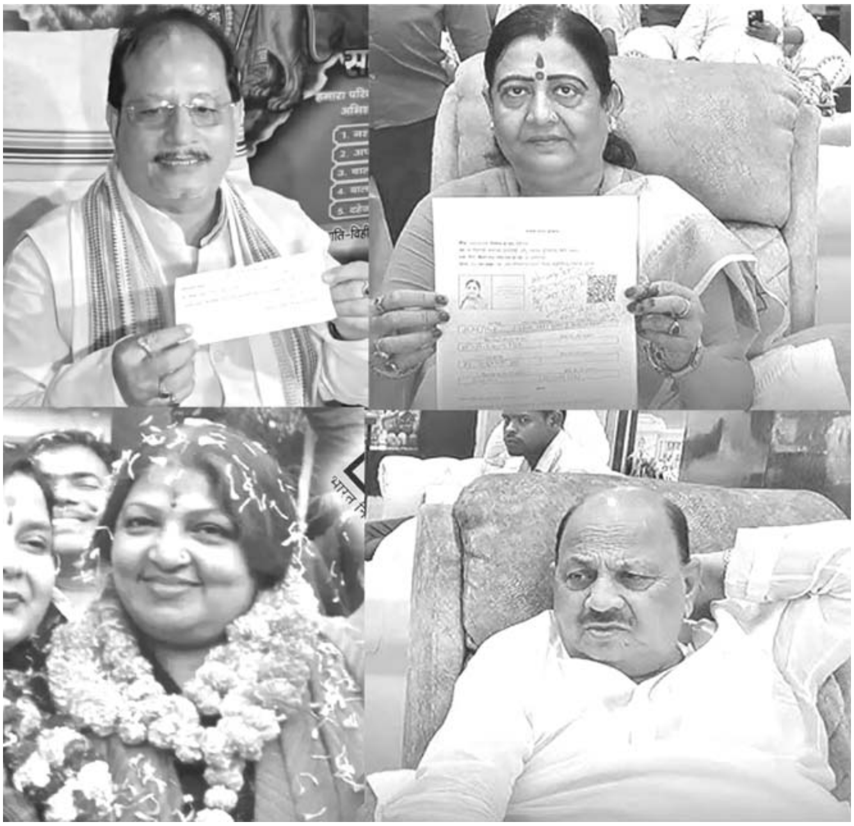

लिए लड़ाई लड़ी। हम जो मांग लगातार उठा रहे थे, उन्हें अब उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत का यह फैसला लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करेगा।" उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 65 लाख से अधिक मतदाता, जिनके नाम हटा दिए गए थे, निर्वाचन आयोग अब उनसे संबंधित जानकारी बूथ-वार प्रदान करेगा, जिसमें मृत मतदाताओं, स्थानांतरित व्यक्तियों और उन लोगों के बारे में डेटा शामिल होगा, जिनके नाम गलती से लापता श्रेणी में जोड़ दिए गए थे या हटा दिए गए थे। राजद नेता ने कहा कि एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद यह मामला पहली बार 27 जून को उठाया गया था और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का कभी भी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रहा है। तेजस्वी ने कहा कि अंतरिम आदेश ने निर्वाचन आयोग की बेईमानी, धोखाधड़ी और जानकारी छिपाने की प्रवृत्ति को भी उजागर कर दिया है। अब आयोग के कामकाज का सच सामने आ गया है। हम निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इस तरह की गड़बड़ियों को उजागर करते रहेंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी पार्टी अब "हाईटेक" हो गई है। उन्होंने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का एकजुट होकर विरोध करने के लिए विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के नेताओं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और शरद पवार का आभार जताया। राजद नेता ने कहा कि लोग जानते हैं कि जब यह खुलासा हुआ कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सांसद वीणा देवी, जदयू के विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह, मुजफ्फरपुर के महापौर और अन्य भाजपा नेताओं के पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र हैं, तब निर्वाचन आयोग कैसे चुप रहा। उन्होंने कहा, मेरा मजाक उड़ाया गया और राजग नेताओं ने मेरे रुख के लिए मुझे गालियां दीं। लेकिन निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बना रहा; मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं राजग नेताओं को बिहार में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की उनकी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। तेजस्वी ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, "एक बिहारी, सब पर भारी।" उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में राजग को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए और बिहार की जनता को परेशान करने के लिए किया। लेकिन जनता ने अपनी एकता से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ है। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश तब उजागर हुई, जब एसआईआर पर सुनवाई के दौरान मृत मतदाताओं को शीर्ष अदालत के समक्ष यह साबित करने के लिए पेश किया गया कि वे जीवित हैं। उन्होंने दावा किया कि अज्ञात स्रोतों का इस्तेमाल करके झूठी खबरें चलाई गईं, लोगों को घुसपैठिया बताया गया और 'मीडिया ट्रायल' के दौरान व्यक्तिगत हमले किए गए। तेजस्वी ने कहा कि एक बार बूथवार सूची सार्वजनिक हो जाए, तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोगों को घुसपैठिया बताने की राजनीति का भी पर्दाफाश हो गया है। राजद नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में एक भी घुसपैठिये का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के मतदाताओं को बिहार में पंजीकृत किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के बिहार प्रभारी भीखूभाई दलसानिया, जो गुजरात के रहने वाले हैं, पटना में मतदाता बन गए हैं, जबकि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर में मतदान किया था। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सभी नेता बिहार के रोहतास जिले से 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू किया है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें सच्चाई बताई जा सके।

बहरहाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का

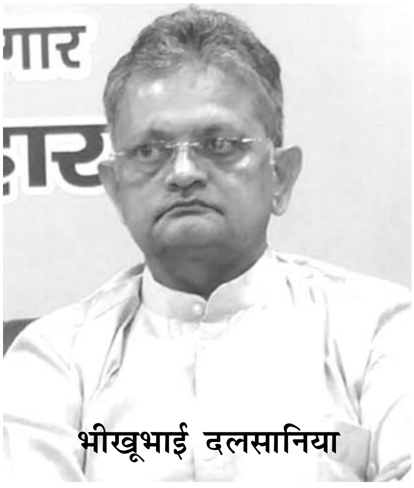

भीखूभाई दलसानिया

विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दल आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना चाहिए अन्यथा उनके 'वोट चोरी' के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है और शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वह केवल शपथ लेकर गवाह के रूप में ही ऐसा कर सकता है। निर्वाचन आयोग का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने 'वोट-चोरी' के खिलाफ चुनावी राज्य बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने संबोधित करते हुए दोहरे मतदान और 'वोट चोरी' के आरोपों को निराधार करार दिया तथा कहा कि सभी हितधारक पारदर्शी तरीके से एसआईआर को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा बिहार में एसआईआर के समय पर सवाल उठाए जाने पर कुमार ने कहा कि यह एक मिथक है कि

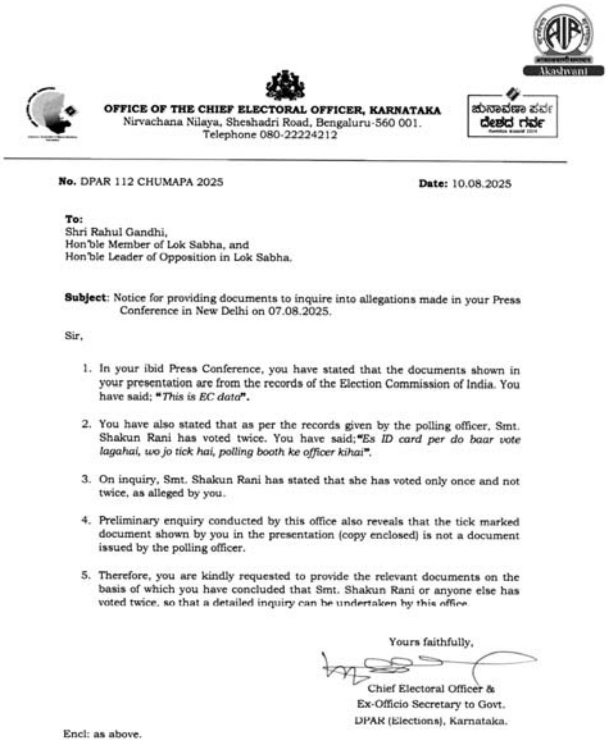

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, KARNATAKA
Nirvachana Nilaya, Sheshadri Road, Bengaluru-560 001.
Telephone 080-22224212

No. DPAR 112 CHUMAPA 2025 — Date: 10.08.2025

To:
Shri Rahul Gandhi,
Hon'ble Member of Lok Sabha, and
Hon'ble Leader of Opposition in Lok Sabha.

Subject: Notice for providing documents to inquire into allegations made in your Press Conference in New Delhi on 07.08.2025.

Sir,

1. In your ibid Press Conference, you have stated that the documents shown in your presentation are from the records of the Election Commission of India. You have said: "*This is EC data*".
2. You have also stated that as per the records given by the polling officer, Smt. Shakun Rani has voted twice. You have said; "*Es ID card per do baar vote lagahai, wo jo tick hai, polling booth ke officer kihai*".
3. On inquiry, Smt. Shakun Rani has stated that she has voted only once and not twice, as alleged by you.
4. Preliminary enquiry conducted by this office also reveals that the tick marked document shown by you in the presentation (copy enclosed) is not a document issued by the polling officer.
5. Therefore, you are kindly requested to provide the relevant documents on the basis of which you have concluded that Smt. Shakun Rani or anyone else has voted twice, so that a detailed inquiry can be undertaken by this office.

Yours faithfully,

Chief Electoral Officer &
Ex-Officio Secretary to Govt.
DPAR (Elections), Karnataka.

Encl: as above.

एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करना निर्वाचन आयोग का कानूनी कर्तव्य है। उन्होंने कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल और उनके नेता बिहार में एसआईआर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों से बिहार में मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह करता है। अभी 15 दिन बाकी हैं। कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं तथा बूथ स्तर के अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता तथा सत्तारूढ़ और विपक्षी दल, दोनों ही चुनाव प्राधिकार के लिए समान हैं। उन्होंने कहा, अगर चुनाव याचिकाएं 45 दिन के भीतर दायर नहीं की जातीं, लेकिन वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं, तो यह भारतीय संविधान का अपमान है। कुमार ने कहा कि न तो आयोग और न ही मतदाता दोहरे मतदान और 'वोट चोरी' के निराधार आरोपों से डरते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग कुछ लोगों द्वारा खेली जा रही राजनीति की परवाह किए बिना सभी वर्गों के मतदाताओं के प्रति दृढ़ रहेगा। उन्होंने सवाल किया, चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में 'वोट चोरी' हो सकती है? यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कांग्रेस द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों के बाद अपना हमला तेज कर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत से पहले आयोजित सभा में यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि पूरे देश में वोट की चोरी की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कई दलों की शिकायतों और देश के भीतर मतदाताओं के प्रवास के मद्देनजर नवीनतम एसआईआर आवश्यक हो गया था। उन्होंने कहा कि

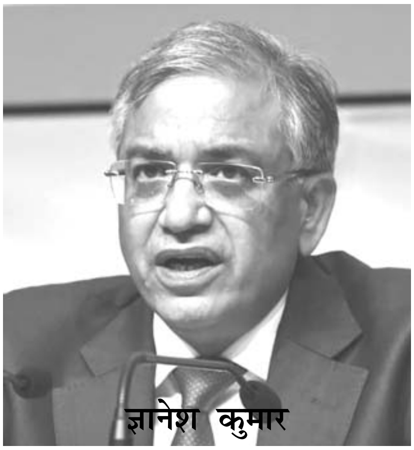

ज्ञानेश कुमार

पवन खेड़ा

कन्हैया कुमार

जाने-अनजाने में, प्रवास और अन्य समस्याओं के कारण कुछ लोगों के पास कई मतदाता पहचान पत्र हो गए। यह एक मिथक है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया गया है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियों में सुधार करना निर्वाचन आयोग का कानूनी कर्तव्य है।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुआ कहा कि पहले निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है और इसके बाद पार्टी भी हलफनामा देकर बताएगी कि इसमें गड़बड़ है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त की धमकियों से डरने वाली नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने दावे को लेकर हलफनामा दें या फिर माफी मांगें। खेड़ा ने कहा कि इस देश का निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह बहुत परेशानी वाली बात है। खेड़ा ने कहा, वोटर अधिकार यात्रा का असर यह है कि इसकी शुरुआत होते ही ज्ञानेश कुमार गुप्ता को संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा। जब कल वह प्रकट हुए तो धमकी दी कि हलफनामा दो या माफी मांगो। वह शायद भूल गए कि हम धमकियों से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने ही कागजात पर भरोसा नहीं है। खेड़ा ने कहा कि इस देश का निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वह बहुत परेशानी वाली बात है। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा संविधान की चोरी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव सर्वेक्षण में कहा गया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे उलट आए। कुमार ने कहा कि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची की मांग की। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग अपने ही तर्कों में फंस गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग हलफनामा मांग रहा है क्योंकि उसे अपने ही कागज पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग देश की जनता की आंखों में आंकड़े झोंकना चाहता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है और इसके बाद कांग्रेस भी हलफनामा देकर बताएगी कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा साफ नहीं है और वह सर्वोच्च नेता का चेहरा चमकाने में ज्यादा व्यस्त है। कुमार ने दावा किया कि कागज के नाम पर असल मतदाताओं को परेशान किया गया।

बताते चले कि राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन भी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा और चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र और बिहार में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बनने पर वोट चोरी के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं उसी तरह निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एससआईआर) के रूप में विशेष पैकेज लेकर आया, जिसका मकसद नए ढंग से वोट चोरी करना है। उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी के जरिए भारत माता पर आक्रमण किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग उनसे हलफनामा मांग रहा है, लेकिन जनता इस आयोग से हलफनामा मांगेगी, क्योंकि जल्द उसकी चोरी पूरे देश में पकड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने दूसरे दिन की यात्रा औरंगाबाद के कुटुंबा से शुरू की, जो रफीगंज होते हुए गयाजी जिले पहुंची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद स्थित मशहूर देव सूर्य मंदिर के दर्शन किए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जगह-जगह लोग सड़क के किनारे कतारबद्ध खड़े थे और लोगों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। राहुल गांधी ने पहले सासाराम और फिर औरंगाबाद में ऐसे कई लोगों से मुलाकात की, जिनके नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से काट दिए गए, जबकि

उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए कहा, निर्वाचन आयोग यह कहता है कि एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दो, जबकि जिम्मेदार वह है, चोरी उनकी पकड़ी गई। मुझे कहते हैं कि हलफनामा लाओ। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। हम हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी चोरी पकड़ेंगे और देश को दिखाएंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, जैसे मोदी जी बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे ये बिहार के लिए नया विशेष पैकेज लाए हैं, उसका नाम एसआईआर है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एसआईआर का मतलब नए तरीके से चोरी करना है। राहुल गांधी का कहना था कि जनता का वोट चोरी किया जा रहा है, इसलिए यात्रा निकाली गई है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा, मैं जो कहता हूं वह करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता..तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें। अभी नरेन्द्र मोदी की सरकार है और आप उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बारिश के बीच जनता को संविधान की प्रति दिखाते हुए दावा किया कि यह भारत माता का संविधान है और जब नरेन्द्र मोदी तथा निर्वाचन आयोग वोट चोरी करते हैं,

तो वे भारत माता और संविधान पर आक्रमण करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग को भारत माता और संविधान पर आक्रमण करने नहीं देंगे। निर्वाचन आयुक्तों सुन लीजिए, अगर सही काम नहीं किया, तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। बाद में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, वोट चोरी... संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण है। वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है। हम न तो निर्वाचन आयोग और न ही मोदी को हमारी भारत माता और संविधान पर हमला करने देंगे। उन्होंने सभा में कहा, कई साल से लग रहा था कि चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा और निर्वाचन आयोग ने मिलकर चोरी किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद हमें ये भी पता चला कि भाजपा ने कर्नाटक में भी वोट चोरी की। हमने कर्नाटक में एक विधानसभा सीट की मतदाता सूची की तो पता चला कि वहां एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी अपने दावे को लेकर सात दिन में हलफनामा दें या फिर माफी मांगें और यदि हलफनामा नहीं दिया तो आरोप निराधार माना जाएगा। इस संवाददाता सम्मेलन में दोनों निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद थे।

सनद् रहे कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक कर दिया है। यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर 'एएसडी' (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित कर रहा है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हटाए गए नामों का प्रकाशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुसार, रोहतास, बेगूसराय, अरवल और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर एएसडी सूचियां प्रदर्शित की गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नामों

को हटाने का कारण भी बताया जाए, जैसे कि मृत्यु, प्रवासन या दोहरी प्रविष्टि (डुप्लीकेसी)। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इसके अलावा, यह लिस्ट बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यालयों, ब्लॉक विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में भी प्रदर्शित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस जानकारी का व्यापक प्रचार करने का निर्देश भी दिया था, जिसमें अखबार, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया शामिल हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके नाम दोबारा जोड़ने या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड को भी एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि आधार नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। विडम्बना है कि चुनावी राज्य बिहार में निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्र शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 7.9 करोड़ से घटकर 7.24 करोड़ रह गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पटना में सबसे ज्यादा 3.95 लाख गणना प्रपत्र को मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि मधुबनी में ऐसे गणना प्रपत्र की संख्या 3.52 लाख, पूर्वी चंपारण में 3.16 लाख और गोपालगंज में 3.10 लाख है। आयोग के अनुसार, एसआईआर की कवायद शुरू होने से पहले बिहार में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 7.9 करोड़ बताई गई थी। हालांकि, उसने बताया कि तब से 22.34 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, 36.28 लाख लोग या तो राज्य से स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं या अपने बताए गए पते पर नहीं मिले हैं और 7.01 लाख लोग एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। मसौदा मतदाता सूची ऑनलाइन जारी कर दी गई हैं और राज्य के सभी 38 जिलों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को "दावे और आपत्तियों" के चरण के लिए इनके प्रिंटआउट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह चरण एक सितंबर तक जारी रहेगा और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। पटना में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसी विपक्षी पार्टियों ने मसौदा मतदाता सूची में साझा किए गए विवरण पर असंतोष व्यक्त किया। ये दल आरोप लगा रहे हैं कि इस कवायद का मकसद राज्य विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की मदद करना है।

विदित हो कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप गठबंधन की सरकार बनाइए। हम अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही वोटर अधिकार यात्रा जब नवादा पहुंची तो वहां माहौल पूरी तरह चुनावी जंग में बदल गया। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस दौरान मंच से ऐलान किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एक मजबूत सरकार बनाएगा और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएगा। वही तेजस्वी ने राहुल गांधी की मौजूदगी के लिए आभार जताया और कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार से एनडीए का सफाया किया जाए। इस बार हम सब मिलकर लोकसभा में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा सरकार केवल वोटर लिस्ट से नाम नहीं काट रही, बल्कि पेंशन और राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी लोगों को वंचित कर रही है इस मौके पर राहुल गांधी ने भी मंच से संकेत दिए कि कांग्रेस "वोट चोरी" की सच्चाई जनता के सामने उजागर करने का काम करेगी। बता दें कि 'वोटर अधिकार यात्रा' में सुबोध कुमार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को 'वोट चोरी' की कहानी बताई। सुबोध ने बताया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। इतना ही नहीं, मैं लोकसभा चुनाव में पोलिंग एजेंट भी था। वही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपने भाषण में कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर पहले आपका वोटर कार्ड छीना। उसके बाद राशन कार्ड छीन लिया जाएगा। फिर आपकी जमीनें अडानी-अंबानी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये देश चुनिंदा पूंजीपतियों का नहीं है। ये देश युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों का है, लेकिन यहां सारा काम पूंजीपतियों के लिए होता है। इसलिए हमें ये हालात मिलकर बदलने हैं।

बहरहाल, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पिछली बार की तुलना में कुछ खास होने जा रहे हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि हर

चुनाव में मतदाताओं संख्या में इजाफा होता है, लेकिन बिहार में इस बार 2020 के मुकाबले मतदाताओं की संख्या कम रहने वाली है। इस बार 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। निश्चित रूप से इसका व्यापक असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत बिहार के अन्य विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की मतादात सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में मतदाता अपने वोट के हक से वंचित रह जाएंगे। राहुल गांधी तो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम भी पाए गए हैं। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी वोटरों को हटाकर और योग्य मतदाताओं को जोड़कर मतदाता सूची को शुद्ध करना है। इससे चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। चूंकि इस चुनाव में 65 लाख मतदाता कम होने की बात कही जा रही है, ऐसे में राज्य की सभी 243 सीटों पर औसतन करीब 25000 वोट कम हो जाएंगे। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 150 के लगभग ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां जीत का अंतर 25 हजार या उससे नीचे रहा है। इनमें 25 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां हार-जीत का अंतर 5000 या उससे कम रहा था। करीब 18 सीटों पर परिणाम 3000 से भी

कम वोटों के आधार पर तय हुआ। आधा दर्जन सीटें ऐसी भी थीं, जहां हार-जीत का फासला महज 1000 वोटों से भी कम रहा है। वही राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो यदि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से यदि हटाए गए मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थक हैं या किसी समुदाय से संबंधित हैं तो इससे वोटों का समीकरण बदल सकता है। दूसरी ओर, नए और योग्य मतदाताओं के जुड़ने से भी चुनावी परिदृश्य में बदलाव आ सकता है। इस प्रक्रिया में कुछ जटिलताएं भी देखने को मिल रही हैं। इस बार नए आवेदकों को अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता की घोषणा और जन्मतिथि और स्थान का प्रमाण देना होगा। यदि वे भारत के बाहर पैदा हुए हैं, तो उन्हें भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण या नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण देना होगा। राज्य में वर्तमान में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि भाजपा एक सीट के अंतर से दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर है। बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 122 सीटों की जरूरत रहेगी। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि मतदाताओं की संख्या घटने का लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलेगा या विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन एक बार जरूर तय है कि इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ●

फिर पलटा सुप्रीम कोर्ट

कुत्ते मामले में सुप्रीम कोट का फैसला अजब-गजब

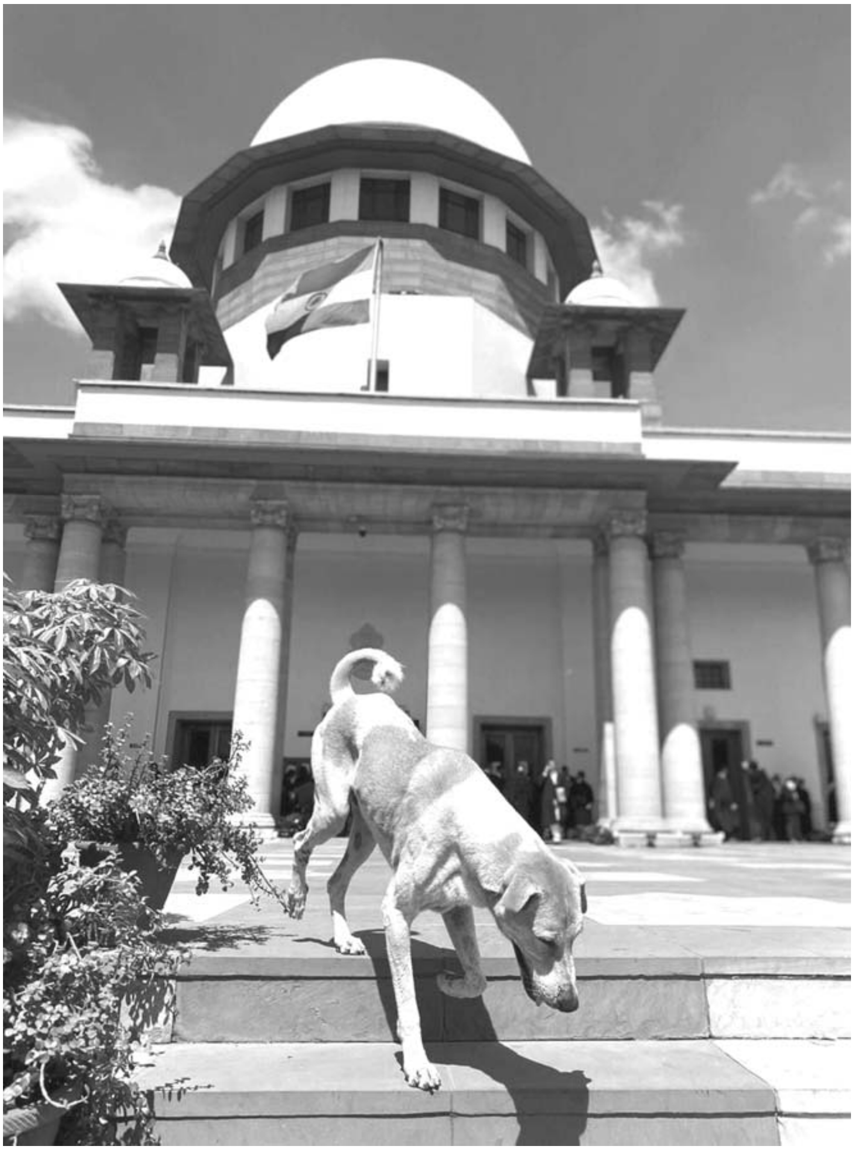

● संजय कुमार सिन्हा

अपने ही फैसले को बदल दिया सुप्रीमकोर्ट ने 11अगस्त, 2025 के फैसले सुप्रीमकोर्ट के दो जजों जेबी पार्डीवाल एवं आर महादेवन ने किया था अब तीन न्याय के मुर्ति जज संदीप मेहता विक्रम नाथ व एनवी अंजारिया ने उसी फैसलों लगभग पलट दिया। फैसले पटल में वही बात है जो लगभग पहले से व्यवस्था में चली आ रही थी, जैसे कुत्तों पकड़ कर नशबंदी कर के उसी जगह पर छोड़ देना ये सब तो पहले से ही नगर निगम पालिका परिषद कर ही रही थी, फिर भी उसी बातों को प्रतिशत में बाट दिया गया कि अब 70 प्रतिशत कुर्तो को ही नशबंदी किया जायेगा। क्या बचे हुए 30 प्रतिशत कुत्ते लोगों को काट नहीं सकतीं क्या? ये अधुरा बेकार नासमझ फैसला सिर्फ मात्र 0.02 प्रतिशत कुत्ते प्रेमी गैंग को खुश करने और अपने वफादार वकील कपिल सिब्बल मनुषेक सिघवी को खुश करने की कार्य फिर से सुप्रीमकोर्ट ने किया है। दुनियां के किसी देशों में इतने लावारिस कुत्ते सड़क गलीयो में नहीं होतें जितनी भारत के एनसीआर में उपलब्ध हैं, इस कुर्तो की वजह से पर्यटन उद्योग को भी भारी नुकसान बहुत समय से हो रही है, दिल्ली एनसीआर में लोगों सब एक छोटे से मकान में रहते हैं न छत उनकी न समुचे पार्किंग उनकी एक खोली में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छोटे बच्चों और सिनियर सिटीजन को है जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते इस कुत्ते के डर से ये डर मात्र नहीं है सैकड़ों हजारो की संख्या में कुत्ते के काटने की घटना सिर्फ दिल्ली शहर में हो रही है, एनसीआर को तो छोड़ दें। अब तो कुत्ते से परेशान जनता उस दिन के ईन्तजार में रहेगें की आने वाले समय में पांच सदस्यीय बैंच इसका फैसला करे और कुत्ते को सेन्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाये? और फिर कोई छह सात जजों की बैंच बहाल न हो और कोई कपिल सिब्बल मनुषेक सिघवी पैरवी करने नहीं आवे, परंतु फिलहाल ऐसा हम संतोष कर सकते हैं।

☞ **कोर्ट के आदेश :-** तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उस आदेश के पीछे इरादा नागरिकों को आक्रामक और रैबीज ग्रसित कुत्तों के आक्रमण से बचाना था लेकिन उस आदेश के कुछ पहलू हैं कि जिन्हें संतुलित करने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने उस आदेश पर रोक लगाने का विरोध किया था और मीडिया में आयी खबर के आंकड़े देते हुए कहा था कि 2024 में 3715712 लोगों को कुत्तों ने काटा है। कुत्तों के हमले के भय से बुर्जग और बच्चे बाहर नहीं निकलते।

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आज दिए आदेश में कहा है कि सड़कों से आवारा कुत्तों के पकड़ने उन्हें डॉग शेल्टर में रखने और उनका बंध्याकरण व टीकाकरण करने का 11 अगस्त का आदेश यथावत लागू रहेगा बस उसमें एक ही संशोधन है कि पकड़े गए कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण के बाद सिर्फ रैबीज संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ कर बाकी को उसी जगह वापस लाकर छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आक्रामक और रैबीज

संक्रमित या जिनके रैबीज संक्रमित होने का संदेह है वे कुत्ते किसी भी स्थिति में नहीं छोड़े जाएंगे। संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को बंध्याकरण व टीकाकरण के बाद अलग शेल्टर में रखा जाएगा। कोर्ट ने नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को भोजन कराने का एक निश्चित स्थान बनाएं। यह फीडिंग प्वाइंट उस इलाके में कुत्तों की संख्या को देखते हुए बनाया जाएगा। फीडिंग प्वाइंट के पास एक नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें यह लिखा होगा कि आवारा कुत्तों को सिर्फ इसी जगह खाना खिलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आवारा कुत्तों को सड़क पर भोजन देने की इजाजत नहीं होगी और जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी।

☞ **जारी होंगे हेल्पलाइन नंबर :-** कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश इसलिए जारी किये जा रहे हैं क्योंकि कुत्तों के हमले की घटनाएं उन्हें अनियमित तौर पर सड़कों पर भोजन कराने के कारण घटती हैं और इस निर्देश से यह सुनिश्चित करना है कुत्तों को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भोजन कराने की प्रवृत्ति खत्म हो, क्योंकि ये प्रवृत्ति गलियों और सड़कों पर टहलने वालों के लिए बड़ी परेशानी बनती है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रत्येक नगर निकाय एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी जिसमें इन आदेशों के उल्लंघन की शिकायत की जा सके एवं जैसे ही कोई शिकायत आती है, संबंधित व्यक्ति या एनजीओ के नंबर जारी करेगी जिसमें इन आदेशों के उल्लंघन की शिकायत की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर स्पष्ट किया कि उसके इन निर्देशों के पालन में कोई भी व्यक्ति या संस्था बाधा नहीं डालेगा। अगर कोई आदेश का अनुपालन कर रहे लोकसेवक के काम में कोई बाधा डालता है तो उस पर लोकसेवक के काम में बाधा पहुंचाने के तहत कार्यवाही होगी। कोर्ट ने कुत्ता प्रेमी और पशु प्रेमी व्यक्तियों और एनजीओ के बारे में भी आदेश दिया है और कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करना है तो व्यक्तिगत अर्जी करने वाले को 25000 और एनजीओ को दो लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने होंगे तभी सुनवाई होगी। और इस पैसे का उपयोग आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में होगा।

☞ **गोद लेने का भी ऑप्शन सुझाया :-** कोर्ट ने आदेश में आवारा कुत्तों को गोद लेने की छूट दी है। आदेश में कहा है कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए संबंधित नगर निकाय को अर्जी दे सकते हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो कुत्ता उन्होंने गोद लिया है वह सड़क पर वापस नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सभी नगर निकायों को हलफनामा दाखिल कर मौजूदा ढांचागत संसाधनों के आंकड़े जैसे डॉग शेल्टर की संख्या, पशु चिकित्सक, कुत्ता पकड़ने वाले लोग, कुत्ता पकड़ने का विशेष वाहन और पिंजड़े आदि की संख्या बताने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशुपालन विभाग के सचिवों और स्थानीय निकायों के सचिवों के जरिए पक्षकार के तौर पर जोड़ने का आदेश दिया है ताकि उनके यहां एबीसी रूल लागू करने के बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आवारा कुत्तों की समस्या से संबंधित लंबित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर ली हैं। जिन पर इस मामले के साथ ही सुनवाई की जायेगी कोर्ट ने आठ सप्ताह बाद फिर से अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है, मामले की सुनवाई फिर दो महीने बाद होगी।●

राजनीतिक गलियारों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश में अगले साल संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने गांव से लेकर शहर तक राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी भले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन गाँव-गाँव में चौपाल सजने लगी हैं। चाय की दुकानों, पंचायत चौपालों और खेतों के किनारों पर अब सिर्फ फसल और महंगाई की नहीं, बल्कि प्रधान बनने की रणनीतियों की बातें हो रही हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहे हैं। पंचायती चुनाव की महत्ता की बात की जाये तो पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य था ''गाँव का शासन गाँव के हाथ में''। एक तरफ गांव में चौपालें सज रही हैं तो दूसरी तरफ इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बदली हुई आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की सुगबुगाहट के चलते चुनाव लड़ने के इच्छुक कई नेताओं उम्मीदवारों की पेषानियों पर बल पड़ गये है। ऐसा इस लिये है क्योंकि हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट कहा था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया 2015 को आधार वर्ष मानकर लागू की जाये, इसी के साथ कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई आरक्षण सूची को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले ने न केवल योगी सरकार की किरकिरी कराई बल्कि नई चुनौतियाँ भी खड़ी कीं हैं, वहीं हाईकोर्ट के फैसले ने ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी गणित को भी पूरी तरह बदल दिया।

बहरहाल, पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लंबे समय से विवादास्पद रहा है। इस बार भी, जब सरकार ने नई आरक्षण नीति लागू करने की कोशिश की, तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नई आरक्षण नीति पारदर्शी नहीं है और यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि आरक्षण की व्यवस्था 2015 के आधार पर ही लागू की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले का असर ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों पर पड़ना तय है। कई उम्मीदवार, जो पहले से अपनी जीत की रणनीति बना चुके थे, अब नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गए। खास तौरपर, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण रहा। हाईकोर्ट के इस आदेश ने यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण का रोटेशन चक्रानुक्रम (रोटेशनल) तरीके से हो, जिससे हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके बाद ही योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में 2015 के अनुसार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने

ओम प्रकाश राजभर

अनुप्रिया पटेल

अरूण राजभर

हेतु एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का फैसला किया है। यह आयोग सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा और आरक्षण नीति को और मजबूत करने के लिए सुझाव देगा। इस कदम को सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत कुछ आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनाव को और जटिल बना सकती है। कोर्ट के पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़ें फैसले ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित किया, बल्कि ग्रामीण मतदाताओं के बीच भी एक नई बहस छेड़ दी। कई लोग इसे सामाजिक न्याय की जीत मान रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि बार-बार बदलती नीतियों से चुनावी प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ रही है। अब, पंचायती राज विभाग को नई आरक्षण सूची तैयार करने और कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की चुनौती है। ऐसे में चुनाव कराये जाने में देरी भी हो सकती है। उधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नये सिरे से आरक्षण की व्यवस्था के बीच प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा 2026 के जनवरी और फरवरी माह में होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है और संबंधित विभागों को समय पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इन चुनावों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव की तिथियां देशभर के अन्य चुनावों और बोर्ड परीक्षाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दी जाएंगी। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव के लिये सबसे खास बात यह है कि यह संभवतः यह चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराये जा सकते हैं। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि गाँव की 'सरकार' बनाने के लिये से प्रदेश की 'राजधानी' लखनऊ तक में 'पंचायतों' का दौर चल रहा है। सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व पूरी दमखम के साथ जुटा हुआ है क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजों से 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिये भी 'मैसेज' निकलेगा। एक समय था जब पंचायत चुनाव में राजनैतिक दल प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं लेते थे, लेकिन अब करीब-करीब सभी राजनैतिक दल अपने प्रत्याशी उतारने से गुरेज नहीं करते हैं। यही वजह है कुछ राजनीतिक दल आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने पंचायत चुनावों में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने इसे 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल करार दिया है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। सुभासपा छड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और 15 जून तक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगी। वहीं अपना दल की नेत्री और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी पंचायत चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा करके बीजेपी खेमें में हलचल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां और राजनीतिक दलों की सक्रियता आगामी चुनावों के संकेत दे रही हैं।

गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव न केवल लोकतंत्र का सबसे निचला लेकिन सबसे प्रभावी स्तर है, बल्कि यह सामाजिक समीकरणों, जातीय राजनीति और स्थानीय विकास की बुनियाद भी तय करता है। हर गाँव में प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों के लिए दावेदार तैयार हो रहे हैं। कुछ पुराने चेहरे एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं तो कुछ युवा नए उत्साह के साथ राजनीति में कदम रखने को तैयार हैं। इन चुनावों में जितनी भूमिका वादों और विकास की होती है, उतनी ही भूमिका जातीय समीकरणों, परंपराओं, स्थानीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों की भी होती है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव, विधानसभा या लोकसभा चुनाव से भी कहीं अधिक जटिल और व्यक्तिगत माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाँवों में

पंचायत चुनावों का गणित अक्सर जातीय आधार पर तय होता है। जैसे ही आरक्षण सूची घोषित होती है, उम्मीदवारों की रणनीति बदल जाती है। जिस सीट पर पिछली बार किसी एक जाति का दबदबा था, इस बार अगर वह सीट आरक्षित हो जाए तो समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। इसके अलावा गाँव की राजनीति में 'रिश्तेदारी की राजनीति' भी गहरी होती है। किसी मोहल्ले या टोले से एक से अधिक प्रत्याशी आ जाएँ तो वोट कटने लगते हैं और तीसरा व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले उम्मीदवार एक-दूसरे को मनाने में लग जाते हैं कि ''इस बार तुम नहीं, अगली बार सही''। आगामी पंचायत चुनाव के लिये इस बार यह भी देखा जा रहा है कि महिलाएं और युवा अधिक सक्रिय हैं। महिला आरक्षण के चलते कई महिलाएं अब केवल ''नाममात्र की प्रधान'' नहीं रहना चाहतीं, बल्कि खुद निर्णय लेने और गाँव के विकास में योगदान देने को तैयार हैं। वहीं युवा वर्ग भी परंपरागत राजनीति से हटकर नए मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं को चुनावी मंच पर ला रहा है। कई गाँवों में युवाओं के समूह ''बदलाव मंच'' या ''युवा पंचायत'' जैसे नामों से सक्रिय होकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जबकि पहले के समय में पंचायत चुनाव प्रचार घर-घर जाकर या चौपालों में बैठकर होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के जरिए अब प्रत्याशी अपनी छवि गाँव से बाहर तक भी बना रहे हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार पुराने तरीकों जैसे लाउडस्पीकर, पम्पलेट, बैनर और भंडारे का भी सहारा ले रहे हैं। हालांकि, इसके साथ ही ''प्रलोभनों की राजनीति'' भी सामने आ रही है। जबकि चुनाव से पहले शराब, पैसा, गिफ्ट और वादों का खेल भी गाँवों में देखा जा रहा है। यह न केवल चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करता है।

पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और हकीकत को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। चुनाव के दौरान लगभग हर प्रत्याशी गाँव के विकास की बात करता है-जैसे पक्की सड़कें, साफ-सफाई, नाली व्यवस्था, बिजली, जल आपूर्ति और सरकारी योजनाओं की सही क्रियान्वयन। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अधिकांश वादे फाइलों में दबकर रह जाते हैं। परंतु अब स्थिति बदली है गाँवों के लोग अब पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं। वो अब सवाल करते हैं "पिछले पाँच साल में आपने क्या किया?", "राशन योजना में घोटाला क्यों हुआ?", "ग्राम निधि का सही उपयोग हुआ या नहीं?" इस तरह के सवाल प्रत्याशियों को अब झेलने पड़ रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पंचायत चुनाव के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने की तैयारियां जारी हैं। इसी के तहत पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों के वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया में जुटा है। जनसंख्या के अनुसार वार्डों का गठन किया जाएगा। 1000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड, 2000 पर 11 वार्ड, 3000 पर 13 वार्ड और अधिकतम 15 वार्ड निर्धारित किए जाएंगे। चूंकि इस बार 512 ग्राम पंचायतें समाप्त हो रही हैं, ऐसे में वार्डों की संख्या में भी कमी आने की संभावना है। ग्राम पंचायतों की संख्या घटने से जिला पंचायत सदस्य सीटों में भी कुछ कमी का अनुमान है।

आयोग राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके प्रभावों का समकालीन, सतत और अनुभवजन्य अध्ययन करेगा। आयोग उपलब्ध रिकॉर्ड, रिपोर्टों, सर्वेक्षणों और अन्य आंकड़ों का विश्लेषण कर यह पता लगाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों का अनुपात कितना है। साथ ही, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में अध्ययन करते हुए आयोग शासन को अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट तीन माह के भीतर या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सौंपी जाएगी।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

सपा में काफी पुराना है महिला अपमान का सिलसिला

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

समाजवादी पार्टी (सपा), जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी मुलायम सिंह यादव की तूती बोलती थी। लेकिन समय-समय पर इस पार्टी पर महिलाओं का सम्मान न करने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। यह सिलसिला मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक जारी है। महिलाओं का अपमान करने के तमाम आरोप न केवल पार्टी नेताओं के बयानों से उपजे हैं, बल्कि उनके कार्यों और नीतियों से भी जुड़े हैं। विपक्षी दल, खासकर भाजपा इन मुद्दों को उठाकर एसपी को महिला विरोधी करार देती रही है। समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के अपमान के तमाम ऐसे आरोप लगे, जो समय-समय पर पार्टी की छवि को धूमिल करते रहे।

सबसे चर्चित उदाहरण 2014 का है, जब मुलायम सिंह यादव ने मोरादाबाद में एक रैली के दौरान बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा पर सवाल उठाते हुए कहा था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस बयान ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। मीडिया और महिला अधिकार संगठनों ने इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बताया, क्योंकि यह बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को गलती मानकर हल्का कर रहा था। मुलायम के इस बयान की वजह से सपा पर आरोप लगा कि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेती। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे प्रो-रेपिस्ट रुख बताया, जिससे पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा।

महिलाओं के अपमान को लेकर सपा के एक और प्रमुख नेता आजम खान भी विवादों में घिरे रहे हैं। 2019 में रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान, आजम ने भाजपा उम्मीदवार जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने खाकी अंडरवियर का जिक्र किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे अत्यंत अपमानजनक बताते हुए नोटिस जारी किया। इससे पहले, संसद में भाजपा सांसद रमा देवी पर भी आजम ने सेक्सिस्ट कमेंट किया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इन बयानों ने एसपी पर आरोप लगाया कि पार्टी के नेता महिलाओं को सम्मान नहीं देते और चुनावी फायदे के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

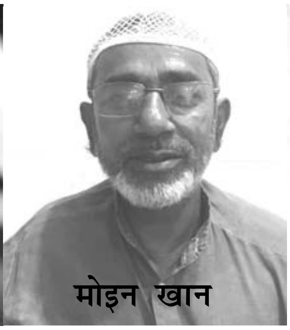

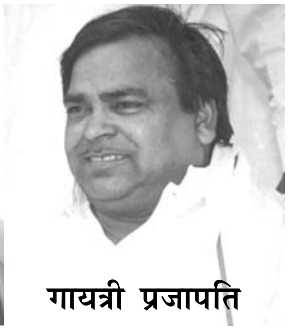

2017 के विधानसभा चुनावों में सपा पर और बड़ा आरोप लगा जब कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ। एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी ने प्रजापति पर गैंगरेप का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एसपी पर आरोप था कि पार्टी ने आरोपी को संरक्षण दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एसपी को बलात्कारियों का संरक्षक कहा और महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बना। हाल के वर्षों में भी ऐसे आरोप जारी हैं। 2024 में अयोध्या बलात्कार कांड में एसपी नेता मोइन खान पर 12 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने एसपी को महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया, और पुराने बयानों का जिक्र किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि एसपी अपराधियों को बचाती है, जबकि एसपी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। ये घटनाएं सपा की छवि को काफी प्रभावित करती रही हैं। परिणाम यह हुआ कि पार्टी ने जब महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई, जैसे स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, लेकिन आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जब महिलाओं का सम्मान राजनीति का मूल होना चाहिए, तब ऐसे विवादों से समाज में असमानता बढ़ती है। सपा को इन आरोपों से सीख लेकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, वरना राजनीतिक नुकसान जारी रहेगा।

बात आज के माहौल की कि जाये तो 2027 में जबकि सपा उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं तब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की लगातार बनती महिला विरोधी छवि ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सोचने को मजबूर कर दिया है कि वह महिला स्वाभिमान के प्रति ज्यादा लचीला रूख अख्तियार करें। वर्ना 2027 के विधान सभा चुनाव में उनको महिला वोटरों से बड़ा झटका मिल सकता है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में जिस तरह से अखिलेश अपनी ही पार्टी की महिला नेताओं का न केवल अपमान बर्दास्त करते जा रहे हैं बल्कि विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल कर आखिलेश ने यह भी साबित कर दिया है कि उनको यह भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी विधायक पूजा पाल जिसके विधायक पति राजू पाल की माफिया अतीक अहमद ने हत्या करा दी थी, वह अतीक के खिलाफ मुंह खोलें। उनको जिस महिला का सुहाग उजाड़ दिया गया। उसका दर्द समझने की बजाये इस बात की चिंता हो रही है कि अतीक के खिलाफ पूजा पाल के विधान सभा के अंदर दिये गये बयान से मुस्लिम वोटर नाराज नहीं हो जायें। इसलिये बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिये पूजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे पूर्व अखिलेश ने अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव के अपमान पर भी अपना मुंह उस समय बंद रखा था जब डिंपल को एक मौलाना रशीदी ने नंगी कहकर संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का मुद्दा तब गरमाया जब सपा ने विधायक पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के चलते उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। इस एक्शन को सपा नेता सही बता रहे हैं, तो बीजेपी ने अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी इस प्रकरण को महिला-सुरक्षा और न्याय हुआ के रूप में पेश कर रही है। कुल मिलाकर पूजा पाल के रूप में बीजेपी को एक नया ब्रांड एंबेसडर और सपा के पीडीए का काउंटर प्लान मिल गया है। राजू पाल की हत्या के बाद सहानुभूति की जो लहर पूजा पाल के साथ बसपा से सपा की ओर शिफ्ट हुई थी, अब उसका सियासी लाभ बीजेपी भी उठाने की तैयारी में है। बीजेपी, सपा को ओबीसी विरोधी बताने में जुटी है। बीजेपी की रणनीति पूजा पाल के बहाने अखिलेश के सबसे बड़े विनिंग फॉर्मूले पीडीए की हवा निकालने की है। यूपी में पाल-बघेल जाति की पिछड़ों में अच्छी-खासी संख्या है, जो सपा के पीडीए की सियासी रीढ़ मानी जाती है। इस तरह बीजेपी अखिलेश यादव को पाल समाज का विरोधी बताने की कवायद करने में जुटी है।●

डिंपल की तौहीन पर अखिलेश की चुप्पी की मजबूरी

● संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की छवि एक प्रखर नेता के रूप में होती है। अखिलेश खुलकर अपनी बात कहते हैं। यूपी में बीजेपी को समाजवादी पार्टी टक्कर देती रही है, लेकिन अखिलेश की राजनीति का यह एक ही पक्ष है दूसरा पक्ष इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल, बात जब अल्पसंख्यकों से जुड़ी होती है तो अखिलेश यादव अपना मुंह सिल लेते हैं। सत्ता मे रहते अखिलेश तुष्टिकरण की सियासत के चलते सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आतंकवादियों पर से केस वापस लेने तक में गुरेज नहीं किया। इसी तरह लव जेहाद की घटनाओं और धर्मांतरण पर भी सपा प्रमुख चुप्पी साधे रखते हैं, जबकि हिन्दुत्व, आरएसएस, श्री रामलला मंदिर, कावड़ियों और सनातन के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हद तो तब हो गई जब मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में सपा प्रमुख ने

डिंपल यादव

एक मौलाना द्वारा उनकी पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ दिये गये विवादित बयान पर भी चुप्पी साधे रखी। शायद उनको लगता होगा कि यह इम्पारटेंट नहीं है कि डिंपल की बेइज्जती हुई हुई,बलिक इम्पारटेंट यह है कि डिंपल की बेइज्जती करने वाले के खिलाफ मुंह खोलने से सपा का मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है।

गौरतलब हो, इसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी ने न केवल एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, बल्कि सपा के लिए एक गंभीर चुनौती भी खड़ी कर दी है। इस घटना पर अखिलेश यादव की चुप्पी ने न सिर्फ उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सपा के महिला वोट बैंक को भी खतरे में डाल दिया है। यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सपा की रणनीति और छवि के लिए गंभीर

संकट बन सकता है। मौलाना साजिद रशीदी ने 22 जुलाई 2025 को संसद मार्ग स्थित मस्जिद में सपा सांसदों की बैठक के दौरान डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने डिंपल को राजनीतिक हिंदू महिला कहकर उनके साड़ी पहनने पर सवाल उठाए और मस्जिद की तौहीन का आरोप लगाया। इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लखनऊ के विभूतिखंड थाने में सपा नेता प्रवेश यादव ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। प्रवेश यादव ने अपनी तहरीर में कहा, मौलाना साजिद ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पर अमर्यादित टिप्पणी कर पूरे समाज को ठेस पहुंचाई है। यह सिर्फ एक महिला की गरिमा को ठेस नहीं, बल्कि समाज की हर महिला इस टिप्पणी से आहत है, लेकिन अखिलेश ने अंत तक मुंह नहीं खोला।

बहरहाल, इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सपा पर हमला करने का मौका दे दिया। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लखनऊ में पत्रकार वार्ता में कहा, डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी नारी सम्मान पर हमला है। अखिलेश

यादव की चुप्पी सवाल खड़े करती है। क्या उन्होंने सत्ता के लिए अपनी पत्नी का अपमान स्वीकार कर लिया है? उन्होंने यह भी जोड़ा, 'यह एक महिला सांसद की गरिमा पर ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति पर हमला है। सपा का मौन क्या इस सोच की सहमति है कि अब मौलवी उनकी महिला सांसदों की गरिमा तय करेंगे? प्रयागराज में पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी सपा पर तंज कसते हुए कहा, 'अखिलेश तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं। चाहे उनके परिवार या पत्नी का अपमान हो, वे चुप रहते हैं। यह महिलाओं के लिए बड़ा संदेश है कि सपा में उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव की चुप्पी को भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा है। लखनऊ में भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अटल चौक पर होर्डिंग लगाकर अखिलेश को मौन मुखिया करार दिया। होर्डिंग में लिखा था, पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन-बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे? धिक्कार है अखिलेश जी। यह होर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे सपा की मुश्किलें और बढ़ गईं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है, खासकर तब जब सभी दल महिला वोटरों को साधने में जुटे हैं।

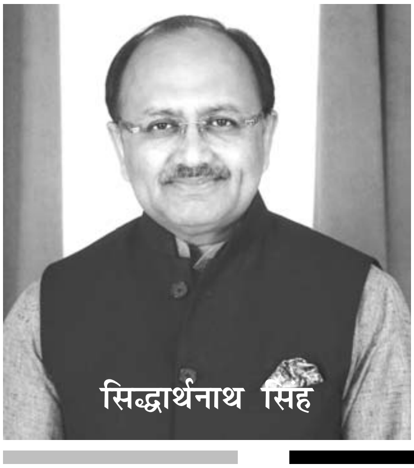
सिद्धार्थनाथ सिंह

बेबी रानी मौर्य

सुभाष यदुवंशी

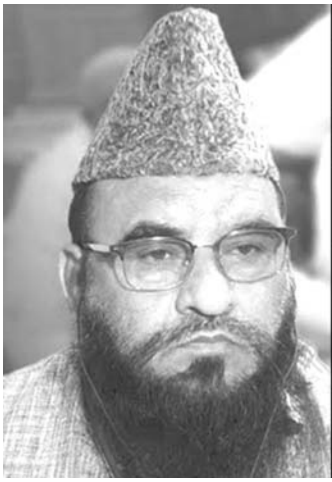

बता दें उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों की भूमिका हाल के चुनावों में निर्णायक रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में महिला केंद्रित योजनाओं जैसे लाडली बहिन और लाड़ली लक्ष्मी का बड़ा योगदान रहा। सपा भी इस तथ्य से वाकिफ है और 2027 के चुनावों के लिए डिंपल यादव के नेतृत्व में महिला वोटरों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। जून 2025 में लखनऊ में सपा की महिला सभा की बैठक में अखिलेश और डिंपल ने बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को संगठित करने और घर-घर जाकर संपर्क करने की योजना बनाई थी। लेकिन मौलाना की टिप्पणी और अखिलेश की चुप्पी ने इस रणनीति को झटका दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश की चुप्पी को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, ताकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो। अखिलेश ने इस मुद्दे पर सीमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लोकसभा में क्या पहनकर आएं, बताओ। जो लोकसभा में पहनकर आएंगे, वो ही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। यह बयान उनके आक्रामक रुख से इतर रहा, जो आमतौर पर वे अन्य मुद्दों पर दिखाते हैं। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी इस मुद्दे को तूल देकर धार्मिक ध्रुवीकरण से बचना चाहती है, लेकिन यह चुप्पी महिला वोटरों को पार्टी से दूर कर सकती है। महिला वोटरों का सपा से मोहभंग होने का खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक था। ऐसे में, डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी और उस पर सपा की नरम प्रतिक्रिया से महिला वोटरों में नाराजगी फैल सकती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां डिंपल की सादगी और साड़ी पहनने की शैली को महिलाएं पसंद करती हैं, यह विवाद सपा की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। भाजपा ने इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाकर सपा को घेरने की कोशिश की है। 28 जुलाई को एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाया। लखनऊ में भाजपा की महिला इकाई ने भी अखिलेश की चुप्पी पर रोष जताया। सपा के लिए यह स्थिति इसलिए भी नुकसानदायक है क्योंकि पार्टी पहले से ही तुष्टिकरण के आरोपों से जूझ रही है। डिंपल यादव ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी गरिमा और सादगी ही उनकी ताकत है। इस पूरे प्रकरण में सपा की रणनीति अब तक संतुलन बनाए रखने की रही है, लेकिन यह संतुलन उनकी महिला वोटरों को खोने की कीमत पर भारी पड़ सकता है। अगर सपा इस मुद्दे पर स्पष्ट और आक्रामक रुख नहीं अपनाती, तो 2027 के चुनावों में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी ओर, भाजपा इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश में है, ताकि वह महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। कुल मिलाकर, यह विवाद सपा के लिए एक राजनीतिक संकट बन गया है, जिसका असर आने वाले समय में स्पष्ट होगा। ●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, जिन्हें एके शर्मा के नाम से जाना जाता है, कभी राजनेता नहीं रहे, वह एक पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसी के चलते अक्सर वह ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। अपनी इसी बढ़ बोलेपन वाली कार्यशैली और विवादित बयानों के कारण हाल के दिनों में उर्जा मंत्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी अपने प्रशासनिक अनुभव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी के रूप में पहचाने जाने वाले शर्मा अब बिजली विभाग में कथित लापरवाही, अधिकारियों पर सख्ती और अपने बयानों से उपजे विवादों के कारण सुर्खियों में हैं। उनकी कार्यशैली जहां कुछ लोगों के लिए सुधारवादी और सख्त प्रशासक की छवि बनाती है, वहीं दूसरों के लिए यह विवादों को जन्म देने वाली साबित हो रही है।

एके शर्मा, 1988 बैच के गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी, ने 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर यूपी की राजनीति में कदम रखा तो उन्हें तुरंत विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, कहा यह जाने लगा कि शर्मा को मंत्री भी बनाया जायेगा, ऐसा इसलिये सही भी लग रहा था क्योंकि एके शर्मा मोदी के काफी करीबी थे, लेकिन सीएम योगी ने उन्हें अपने पहले कार्यकाल में जबरदस्त दबाव के बाद भी मंत्री नहीं बनाया। शर्मा मंत्री तब बने जब दोबारा बीजेपी चुनाव जीत कर आई और योगी ने एक बार फिर से शपथ ली। उन्हें ऊर्जा और नगर विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। ऊर्जा और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले शर्मा ने शुरू में अपनी कार्यकुशलता और अनुशासित दृष्टिकोण से सबका ध्यान भी खींचा। उन्होंने बिजली आपूर्ति में सुधार और विभागीय भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में कई कदम उठाए। हालांकि, हाल के महीनों में उनकी कार्यशैली और बयानबाजी ने उन्हें विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है।

हाल ही में, शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर जमकर नाराजगी जताई। एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग कोई 'बनिए की दुकान' नहीं है, बल्कि जनसेवा का माध्यम है। इस बयान ने न केवल बिजली कर्मचारियों बल्कि वैश्य समाज के बीच भी विवाद को जन्म दिया। कई संगठनों ने इसे अपने समुदाय पर कटाक्ष मानकर विरोध जताया। शर्मा को सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे केवल जनसेवा और व्यापार के बीच अंतर रेखांकित करना चाहते थे। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया ताकि उनकी बात को सही संदर्भ में समझा जाए। इसके अलावा, शर्मा का बिहार में मुफ्त बिजली योजना पर

दिया गया बयान भी खासा चर्चा में रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बिहार में बिजली फ्री है, लेकिन जब बिजली आएगी ही नहीं तो बिल आएगा ही नहीं, हो गई फ्री। इस बयान ने न केवल बिहार सरकार बल्कि विपक्षी दलों को भी हमला करने का मौका दे दिया। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो गया और शर्मा को फिर से सफाई देनी पड़ी। उनके इस बयान को कई लोगों ने उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमियों को छिपाने की कोशिश के रूप में देखा।

मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने की घटना ने भी शर्मा को असहज स्थिति में डाल दिया। उनके ही कार्यक्रम में 10 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसके बाद पांच वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इस घटना को प्रशासनिक विफलता के रूप में देखा गया और शर्मा की सख्त कार्रवाई ने विभाग में हड़कंप मचा दिया। हालांकि, इस कार्रवाई को कुछ लोगों ने उनकी सख्त प्रशासकीय छवि का हिस्सा माना, तो कुछ ने इसे दिखावटी कदम करार दिया। शर्मा ने हाल ही में बस्ती जिले के एक अधीक्षण अभियंता का ऑडियो वायरल किया, जिसमें अधिकारी एक उपभोक्ता के साथ अमर्यादित बातचीत करते सुनाई दिए। इस ऑडियो को शेयर कर शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। इस कदम से जहां कुछ लोग उनकी पारदर्शिता की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे विभागीय असफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर शर्मा की सक्रियता भी चर्चा का विषय रही है। वे अक्सर अपनी उपलब्धियों और विभागीय सुधारों को एक्स पर साझा करते हैं, लेकिन उनके कुछ बयानों और पोस्ट ने विवाद को हवा दी। उदाहरण के लिए, जय श्री राम के नारे को लेकर उनकी टिप्पणी ने कुछ लोगों को नाराज किया, जिन्होंने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश माना।

कुल मिलाकर शर्मा की कार्यशैली को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। जहां कुछ लोग उनके सख्त रवैये को बिजली विभाग में सुधार की दिशा में जरूरी मानते हैं, वहीं अन्य इसे अनावश्यक रूप से आक्रामक और विवादास्पद मानते हैं। उनके बयानों और कार्रवाइयों ने न केवल विपक्ष बल्कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी असहज किया है। वैसे एके शर्मा का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों का मिश्रण रहा है। उनकी सख्ती और सुधारवादी दृष्टिकोण ने बिजली विभाग में कुछ बदलाव जरूर लाए हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी और कार्यशैली ने उन्हें विवादों का केंद्र भी बनाया है। भविष्य में उनके कदम और बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में उनकी स्थिति को और स्पष्ट करेंगे। ●

देवरे और सुहर्ष की जोड़ी के भ्रष्ट और तुगलकी फरमान ने किया

स्वास्थ्य व्यवस्था का सत्यानाश !

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

जब राज्य का राजा यानी मुख्यमंत्री अपनी क्षमता खोता है तो क्या होता है इसका उदाहरण बिहार में देखने को मिलता है। जब मुख्यमंत्री के खास अधिकारी ने पूर्व मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के दामाद सुहर्ष भगत को राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यपालक निदेशक और उनके निजी सचिव रहे निलेश रामचंद्र देवरे को बीएमएसआईसीएल का प्रबंध निदेशक बना दिया। सुहर्ष भगत तो पहले से ही कर्मचारियों और अधिकारियों से गाली-गलौज और भ्रष्टाचार के लिए नाम कमा ही रहे थे, नीलेश रामचंद्र देवरे बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक बनते ही खुलेआम (PMCH कैंपस में) बिहार को चूतिया कह दिया, जिससे बवाल मच गया। कई संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहां तक की पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी गई।

निलेश रामचंद्र देवरे 2011 बैच के बिहार केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। श्री देवरे बाढ़ के अनुमंडल अधिकारी, रोहतास के अपर समहर्त्ता, बाँका, बेतिया, छपरा और मधुबनी के जिलाधिकारी रह चुके हैं। खास बात यह है कि कुछ दिनों तक कैबिनेट मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और नीतीश के लिए विभीषण सामान रामचंद्र प्रसाद सिंह के निजी सचिव भी रह चुके हैं। बीएमएसआईसीएल में प्रबंध निदेशक बनने के पहले नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, जहां उनके CMD पंकज पाल ने इनकी मनमानी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की तो सरकार की किरकिरी होने लगी और दोनों का स्थानांतरण कर दिया गया। सरकार ने फजीहत से बचने के लिए निलेश रामचंद्र देवरे का भी स्थानांतरण कर दिया। मधुबनी के जिलाधिकारी रहते हुए भी इन्होंने मधुबनी समाहरणालय के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर दिया, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हो गए और लगातार तीन दिनों तक मधुबनी समाहरणालय का कामकाज ठप कर दिया। उनके द्वारा माफी मांगने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली। जब लगा कि इनका दाल अब वहां नहीं गलेगा, उनकी गाली-गलौज वहां के कर्मचारी और जनता नहीं सुनेगा, तो उन्होंने आनन-फानन में वहां से अपना स्थानांतरण करवा लिया। इसी तरह बाँका, सारण और बेतिया में भी ये अपने आदत से बाज नहीं आए और कार्यालय में अमानवीय व्यवहार के साथ-साथ गाली-गलौज करते रहे। इनके एक सोशल मीडिया पोस्ट 'एक्स' के माध्यम से देखा जा सकता है कि यह मराठी और राज ठाकरे से कितने प्रभावी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार को खुलेआम गाली देता है, उसे राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर बैठना सरकार में अधिकारियों की मनमानी को दिखाता है।

अभी हाल में ही जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के निविदा प्रणाली की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आपको बता दे भारत सरकार की योजना राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संचालित होती है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार के पूर्व करीबी रामचंद्र प्रसाद सिंह के दामाद हैं और बिहार में किसी भी स्वास्थ्य उपकरण एंबुलेंस सहित की खरीदारी बीएमएसआईसीएल के माध्यम से होती है, जिसके मुखिया पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के निजी सचिव रहे निलेश रामचंद्र देवरे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के बीच अभी कोल्ड वॉर चल रहा है और एक अधिकारी और जनसुराज

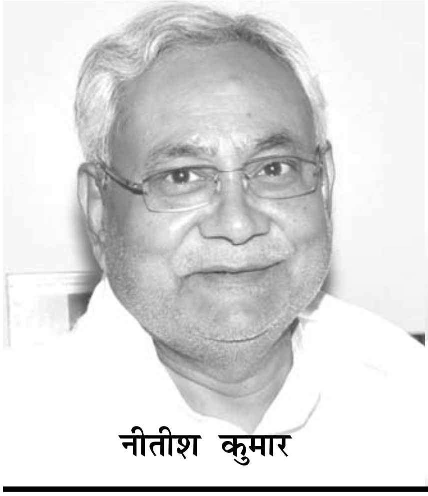
नीतीश कुमार

रामचंद्र प्रसाद सिंह

प्रशांत किशोर

के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह के माध्यम से दोनों अधिकारियों ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सारे कागजात मुहैया कराए थे। नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा बिहारी को सरेआम गाली देने को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने भी इसे गंभीर मामला माना है और नीलेश रामचंद्र देवर को चेतावनी भी दी है। प्रधानमंत्री CPGRAM के रजिस्ट्रेशन नंबर -DOPT/E/2025/0006130 में भी दर्ज मामले में डीओपीटी ने इसे गंभीर मामला माना है।

धीरेंद्र सिंह पासवान, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद, नई दिल्ली) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री मंगल पांडे को पत्र लिखकर बिहार को गाली देने के लिए तत्काल निलेश चंद्र निलेश रामचंद्र देवरे पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं देखा गया। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका संख्या CWJc नंबर-13203/2025 के आलोक में आलेख लिखे जाने तक अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन यह याचिका अखबारों की सुर्खियां जरूर बन गई है। धीरेंद्र सिंह पासवान ने अपने पत्र और याचिका में कहा कि श्री देवरे द्वारा जान बूझकर जरूरी

धीरेंद्र सिंह पासवान

दवाओं की किल्लत की जा रही है एजरूरी स्वास्थ्य उपकरण का क्रय रोका जा रहा है, साथ ही उन्होंने एक तरफ बिहारी कंपनियों को भुगतान लंबित रखे हुए है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कंपनियों का भुगतान अभिलंब करता है। श्री देवरे द्वारा महाराष्ट्र की कंपनियों जैसे नियति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और VASCON इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है और दूसरी तरफ बिहार संवेदककों का भुगतान बेवजह लंबित किया जाता है। बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के प्रबंध निदेशक श्री निलेश रामचंद्र देवरे (भारतीय प्रशासनिक सेवा) द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) परिसर में वाहन पार्किंग को लेकर जहाँ एक ओर अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अत्यंत आपत्तिजनक, जातीय एवं क्षेत्रीय घृणा फैलाने वाला वक्तव्य ***'बिहारी साला चूतिया होता है'*** कहकर सम्पूर्ण बिहारवासियों के आत्म-सम्मान, अस्मिता और गरिमा को गंभीर ठेस पहुँचाई। यह न केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आचरण) नियम, 1968 का स्पष्ट उल्लंघन है, अपितु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'प्रवीन तोगड़िया बनाम भारत सरकार' [W.P.(Crl.) No.-130/2004] तथा 'Tajinder Singh

पीएमसीएच : केमिकल नहीं होने से कई जांच बंद

गरीब मरीजों को निजी लैब में महंगी जांच करानी पड़ रही, तीन माह से परेशानी

इस तरह से परेशान हो रहे मरीज

बेतिया से अपनी 12 वर्षीय बेटी का इलाज कराने आए रोहित राज ने बताया कि दो दिन से परेशान हैं। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने कई ब्लड टेस्ट लिखे। लेकिन पैथोलॉजी विभाग में बताया गया कि इनमें से एक-दो जांच ही हो पाएगी, बाकी के लिए बाहर जाना होगा। नालंदा से अपने भाई का इलाज कराने आए देवेंद्र शर्मा की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने बताया कि पैथोलॉजी विभाग में जाने पर पता चला कि उनके पर्चे में लिखी एक-दो जांच ही यहां होती है। बाकी जांच उन्हें बाहर कराने के लिए कहा गया। इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आईएस ठाकुर के सरकारी मोबाइल पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

निजी पैथोलॉजी में ब्लड जांच का शुल्क

- सिरम इलेक्ट्रोलाइट : 299-520 रुपए
- सीआरपी : 380-1049 रुपए
- थायराइड (T3, T4, TSH पैकेज के लिए) : 399-600 रुपए एबीजी (इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी शामिल हो सकता है) : 1500-1800 रुपए
- विटामिन डी और बी12 का एक साथ पैकेज : 699 रुपए
- केवल विटामिन बी12: 549-1669 रुपए
- केवल विटामिन डी : 649 रुपए
- एलटी-सीसीपी : 1000-1900 रुपए

PMCH में उपलब्ध नहीं है इम्यूनोग्लोबुलिन

इमरजेंसी में पेशेंट को नहीं दी जाती एंटी रैबीज वैक्सीन

patna@inext.co.in

PATNA (18 July): पीएमसीएच में एंटी रैबिज वैक्सीन के लिए मरीज को पांच घंटे तक भटकने से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले को लेकर मरीज की सुध ली. मामले को लेकर अधीक्षक डा. आइएस ठाकुर ने कहा कि अखबार से मामले की जानकारी हुई. सुबह में ही पूरे मामले की जांच कराई. कहा कि एंटी रैबिज इमरजेंसी ड्रग नहीं है. अस्पताल में मरीज उपचार के लिए ओपीडी नहीं गया था, इमरजेंसी या शिशु विभाग में वैक्सीन नहीं रहती है. ओपीडी में एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त इम्यूनोग्लोबुलिन भी उपलब्ध नहीं है. इसके लिए बीएमएससीआइएल को आपूर्ति के लिए इंडेंट किया गया है. आपूर्ति होने के बाद मरीजों को यह उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, टाटा वार्ड में भर्ती मरीज के स्वजन मुन्ना कुमार ने बताया कि शुक्रवार की सुबह पांच बजे उसे डाक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन करीब साढ़े छह बजे अखबार में गुरुवार की घटना से संबंधित खबर को देखकर उन्हें जाने नहीं दिया गया.

बोले विशेषज्ञ : हर समय उपलब्ध होनी चाहिए

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते है कि एंटी रैबिज वैक्सीन बड़े अस्पतालों में हर समय उपलब्ध होने चाहिए; क्योंकि कुत्ता काटने के बाद वैसे यह 24 घंटे के भीतर लगवा लेनी चाहिए, लेकिन यह जितना जल्दी लगे, उतना ही ज्यादा लाभकारी होता है. विशेषज्ञों के अनुसार इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ एंटीबाडी सुरक्षा देता है. यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाया जाता है. यह शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है.

पीएमसीएच में 5 घंटे तक एंटी रैबीज वैक्सीन के लिए भटकती रही बच्ची

भोजपुर में कुत्ता के काटने के बाद जख्मी बच्ची को खरीदकर लगवाना पड़ा इंजेक्शन

patna@inext.co.in

PATNA (17July): भोजपुर से कुत्ता काटने के बाद 10 वर्षीया बच्ची को उपचार व वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे मरीज को पांच घंटा तक भटकने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिली. बाद में बाहर से 1700 रुपये में वैक्सीन लायी गई, इसके बाद उसे दिया गया. अब मरीज को टाटा वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है. भोजपुर के रहने वाले ददन गुप्ता की दस वर्षीय बेटी साजन कुमारी को सुबह आठ बजे कुत्ते ने नोचकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था.

इस कारण बच्ची के जांघ के पास चार जगहों पर घाव बन गए थे और मांस बाहर निकल आया था. स्वजन उसे भोजपुर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां प्राथमिक उपचार कर पीएमसीएच भेज दिया गया. वहां बताया गया कि यहां एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं है. परिजन बच्ची को लेकर पीएमसीएच 12:30 बजे पीएमसीएच आ गए, लेकिन शाम पांच बजे तक इधर से उधर टकराया जाता रहा.

वहां भी उनसे कहा गया कि एंटी रैबिज टीका उपलब्ध नहीं है. चिकित्सक ने बाहर से रैबीशिल्ड (टीका) लाने को कहा. बाहर से 1700 रूपया का इंजेक्शन मंगवाया गया. इसके बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे उसे भर्ती किया गया. मामले को लेकर पूछे जाने पर उपाधीक्षक डा. अरविन्द कुमार सिन्हा ने कहा कि अस्पताल में एंटी रैबीज टीका उपलब्ध है तथा मरीज के परिजन को किसी दलाल ने पैसा ठगने के लिए ऐसा किया गया हो. वहीं, बच्ची के इलाज कराने उनके साथ आए मुन्ना कुमार ने बताया कि डाक्टर की ओर से वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की बात बता कर बाहर से मंगाया गया.

Bagga बनाम भारत सरकार' जैसे मामलों में दिए गए निर्देशों के भी प्रतिकूल है, जिसमें सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा की गई क्षेत्रीय, जातीय अथवा अपमानजनक टिप्पणी को गंभीर अनुशासनात्मक अपराध माना गया है और ऐसे मामलों में राज्य को 'Zero Tolerance' नीति अपनाने की सलाह दी गई है।

बिहार की अस्मिता एवं सांस्कृतिक चेतना पर हमला करने वाली ऐसी प्रवृत्तियों के विरोध में बिहार के युग पुरुष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था : ***'बिहार केवल एक भू-भाग नहीं, वह एक विचार है-जो आत्म-सम्मान, श्रमशीलता और सत्य के लिए खड़ा रहता है।'*** 'लोकनायक जयप्रकाश नारायण का यह वाक्य भी उद्धृत करना समीचीन होगा :- ***बिहार की जनता जब अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो क्रांति जन्म लेती है।'*** इस प्रकार की भाषा और कार्यप्रणाली न केवल इन आदर्शों का अपमान है बल्कि यह बिहार के नागरिकों की सामूहिक गरिमा का हनन भी है।

मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सहित कई विभागों में उनके विरुद्ध दिए हुए आवेदनों पर फेका-फेकी हो रहा है, लेकिन सबूत रहने के बावजूद इन पर कार्रवाई की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। लोग कहते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की लॉबी मजबूत होती है, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार के अधिकारी इन पर कार्रवाई के लिए अब मन बना चुके हैं।

फ्रेंड्स ऑफ बिहारी भैया के द्वारा राजधानी के सड़कों पर पोस्टर साटा गया और पंपलेट बाँटा गया, भोजपुरिया कलाकारों ने भी बिहारी को चूतिया कहने पर इनको चेतावनी देते हुए भोजपुरी में गाना बनाया जो की वायरल हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर होने, पोस्टर सटने और पंपलेट बंटने, गाना वायरल होने और कई न्यूज चैनल के न्यूज वायरल होने के बावजूद मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जांच के आदेश देने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने से इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और यह कर्मचारी और बिहारी को गाली देते आ रहे हैं।

सूत्रों की माने तो इन्होंने महाराष्ट्र में मुंबई पुणे रोड में कई प्लॉट अपने सगे संबंधियों के नाम से खरीदे हैं, जिसका मार्केट प्राइस कई सौ करोड़ रूपया है। एक साथ ही कई कंपनियों के शेयर और कई बड़ी परियोजनाओं में इनका महाराष्ट्र में निवेश है, साथ ही देश के अन्य भागों में भी इनका निवेश है। इन्होंने जो अपना ऐसेट डिक्लेरेशन 2024-25 में दिया, उसमें अपने तथा अपने दो बेटियों के पास कुल जमा और शेयर का कुल रकम 107223957/- रुपया बताया, जबकि अपनी पत्नी के प्रॉपर्टी और जमा रकम का खुलासा इन्होंने अपने एसेट डिक्लेरेशन में नहीं किया। ऐसेट डिक्लेरेशन में इन्होंने अपने नाम से सोने और हिरे की ज्वेलरी का अनुमानित 14 लाख 60 हजार रुपए और अपने दो बेटियों के सोने के ज्वेलरी का मूल्य 41 लाख 60000 रुपया दिखाया और कहा कि उन्हें गिफ्ट के रूप में अपने ग्रैंडपेरेंट से मिला है। ग्रैंडपेरेंट ने इनके बेटियों को 41 लाख 60000 रुपए का सोना गिफ्ट में दिया है, यह तो ग्रैंडपेरेंट आय की जांच करने के बाद ही पता चल सकता है। श्री देवरे अपने ऐसेट डिक्लेरेशन में शेयरों में अपना इन्वेस्टमेंट 13 लाख 11868 रुपया दिखाए।

Declaration of Assets and Liabilities

Year 2024-25

I, **Dr. Nilesh Ramchandra Deore** son of Shree R.D.Deore, Aged 39 years, belonging to **Indian Administrative Service (I.A.S.)** service and presently working as **Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Limited** give herein below the details of the assets (immovable, movable, bank balance, etc.) of myself, my spouse and dependants*:

A. **Details of movable assets**

(Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given)

Sr. No.	Description	Self	Spouse Name(S) (Saee S)	Dependant-1 Name (Ira Deore)	Dependant-2 Name (Sara Deore)
(i)	Cash	Rs. 31,000/-	Smt. Saee S has not created any assets out of my income and we do not any joint property.	Rs. 85,000/-	NIL
(ii)	Deposits in Banks, Financial Institutions And Non-Banking Financial Companies	Savings A/C - Rs. 8,13,787/- Fixed deposits - Rs. 26,83,935/- PPF- Rs. 26,09,930/-		PPF A/C Rs.15,46,000/- Sukanya Samruddhi A/C Rs. 15,78,501/-	PPF A/C Rs.7,06,000/- Sukanya Samruddhi A/C Rs. 7,20,800/-
(iii)	Bonds, Debentures and Shares in companies	Shares of 19 listed companies worth of Rs. 13,11,868/-		NIL	NIL
(iv)	Other financial institutions, NSS, Postal Savings, LIC Policies, etc	LIC Policy Sum Amount Rs. 2,50,000 Yearly premium Rs 9430 paying since 2009		NIL	NIL
(v)	Motor Vehicles (details of make, etc.)	Hero Honda Hunk Year 2008 worth not assessed		NIL	NIL
(vi)	Jewellery (give details of weight and value)	Gold Jewellery around 150 gm worth 12,00,000 Rs Diamond Jewellery worth of around 2,60,000 Rs		Gold Jewellery around 270 gm worth Rs 21,60,000/- received as gift from grand parents.	Gold Jewellery around 250 gm. Worth Rs. 20,00,000/- received as gift from grand parents.
(vii)	Other assets, such as values of claims / interests	Fridge, Micro Oven, Washing Machine, DVD player, Philips Home system, Split AC worth around 1,50,000 Rs Godrej Home furniture includes 2 Complete Bed Room Sets, Modular Kitchen, Sofa, Coffee Table, Sofa Cum bed, Cot etc worth around 4,50,000 Rs Two Laptops both Sony Vaio makes. One apple laptop worth of 1,09,000 Rs	--	--	--

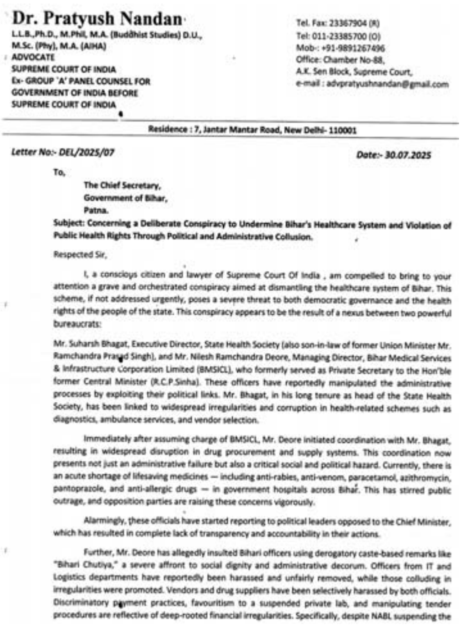

Dr. Pratyush Nandan
L.L.B.,Ph.D., M.Phil, M.A. (Buddhist Studies) D.U.,
M.Sc. (Phy), M.A. (AIHA)
ADVOCATE
SUPREME COURT OF INDIA
Ex- GROUP 'A' PANEL COUNSEL FOR
GOVERNMENT OF INDIA BEFORE
SUPREME COURT OF INDIA

Tel. Fax: 23367904 (R)
Tel: 011-23385700 (O)
Mob-: +91-9891267496
Office: Chamber No-88,
A.K. Sen Block, Supreme Court,
e-mail : advpratyushnandan@gmail.com

Residence : 7, Jantar Mantar Road, New Delhi- 110001

Letter No:- DEL/2025/07 *Date:- 30.07.2025*

To,
The Chief Secretary,
Government of Bihar,
Patna.

Subject: Concerning a Deliberate Conspiracy to Undermine Bihar's Healthcare System and Violation of Public Health Rights Through Political and Administrative Collusion.

Respected Sir,

I, a conscious citizen and lawyer of Supreme Court Of India , am compelled to bring to your attention a grave and orchestrated conspiracy aimed at dismantling the healthcare system of Bihar. This scheme, if not addressed urgently, poses a severe threat to both democratic governance and the health rights of the people of the state. This conspiracy appears to be the result of a nexus between two powerful bureaucrats:

Mr. Suharsh Bhagat, Executive Director, State Health Society (also son-in-law of former Union Minister Mr. Ramchandra Prasad Singh), and Mr. Nilesh Ramchandra Deore, Managing Director, Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited (BMSICL), who formerly served as Private Secretary to the Hon'ble former Central Minister (R.C.P.Sinha). These officers have reportedly manipulated the administrative processes by exploiting their political links. Mr. Bhagat, in his long tenure as head of the State Health Society, has been linked to widespread irregularities and corruption in health-related schemes such as diagnostics, ambulance services, and vendor selection.

Immediately after assuming charge of BMSICL, Mr. Deore initiated coordination with Mr. Bhagat, resulting in widespread disruption in drug procurement and supply systems. This coordination now presents not just an administrative failure but also a critical social and political hazard. Currently, there is an acute shortage of lifesaving medicines — including anti-rabies, anti-venom, paracetamol, azithromycin, pantoprazole, and anti-allergic drugs — in government hospitals across Bihar. This has stirred public outrage, and opposition parties are raising these concerns vigorously.

Alarmingly, these officials have started reporting to political leaders opposed to the Chief Minister, which has resulted in complete lack of transparency and accountability in their actions.

Further, Mr. Deore has allegedly insulted Bihari officers using derogatory caste-based remarks like "Bihari Chutiya," a severe affront to social dignity and administrative decorum. Officers from IT and Logistics departments have reportedly been harassed and unfairly removed, while those colluding in irregularities were promoted. Vendors and drug suppliers have been selectively harassed by both officials. Discriminatory payment practices, favouritism to a suspended private lab, and manipulating tender procedures are reflective of deep-rooted financial irregularities. Specifically, despite NABL suspending the

एकसाथ ही कई पॉलिसी में भी अपना इंवेस्टमेंट दिखाया है। पत्नी की ज्वेलरी और प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाने के बावजूद भी इनके और उनके बेटियों के पास कुल संपत्ति दो करोड़ रूपया के आसपास है जबकि श्री देवरे 2011 बैच के अधिकारी हैं। मात्र 14 साल में उनके पास 2 करोड़ का घोषित बचत है, जबकि पत्नी ज्वेलरी और प्रॉपर्टी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। यह हो ही नहीं सकता है कि कोई पति अपने पत्नी के लिए ज्वेलरी और गिफ्ट नहीं खरीदे। आयकर अधिनियम के तहत कोई अधिकारी जीवनयापन के बाद 30 से 40% ही बचा सकता है, इन्होंने 2011 से अभी तक 14 वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में व्यतीत किया। 14 वर्षों में अधिकतम औसत वेतन 150000 के हिसाब से इनका कुल वेतन 2 करोड़ 52 लाख रुपया हुआ, जिसमें आयकर और सरकार के नियमों को अनुसार इनका कुल बचत 40% के हिसाब से एक करोड़ 80 हजार रुपया हुआ और इन्होंने बचा लिया 2 करोड रुपए के आसपास। जबकि पत्नी की ज्वेलरी और प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाया गया, तब भी इनका बचत 2 करोड़ के आसपास है। अर्थात् यह मामला आय से अधिक का है।

सुहर्ष भगत

नीलेश रामचंद्र देवरे

बीएमएसआईसीएल में इनके प्रताड़ना से कई अधिकारी और कर्मचारी बीमार होकर कार्यालय आना छोड़ चुके हैं। इन्होंने बीएमएसआईसीएल में आईटी मैनेजर मोहित शर्मा को सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उसने एंबुलेंस खरीद से जुड़ी जानकारी GEM पोर्टल से देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके आका रामचंद्र प्रसाद सिंह को एंबुलेंस खरीद का सारा फाइल चाहिए था। इन्होंने बीएमएसआईसीएल का माहौल बेहद ही तनावपूर्ण बना दिया है, इन्होंने अनावश्यक रूप से कई अधिकारियों को अपना शक्ति का दुरुपयोग कर कई बार कारण पिच्छा कर दिया, जो अधिकारी इनके गाली और अपमानजनक शब्दों को नहीं सुनता है उन्हें यह बेवजह परेशान करते हैं। इन्होंने दवाओं की कृत्रिम कमी कर दी है, जिससे कई मरीज दवाओं के अभाव में भटक रहे हैं। कुत्ते काटने की दवा एंटी रेबीज की भारी कमी है, पेरासिटामोल जैसी दवाओं की भी भारी कमी है। अब देखना है कि भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी, पटना उच्च न्यायालय और बिहार सरकार के कई आवेदन के बाद गठित समिति इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि इनके उदंडता और बिहारी को गाली देने की बात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सुशासन पुरुष नीतीश कुमार को भी मालूम है।

दूसरी तरफ जनसुराज के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह के दामाद और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत पर पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पैथोलॉजी की निविदा में हिंदुस्तान वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उससे कम बोली लगाने वाले साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड को निविदा में अयोग्य घोषित करते हुए राज्य का नुकसान पहुँचाया है और राज्य की जनता का पैसा लुटाया है। हम आपके लिए पटना उच्च न्यायालय के आदेश का सारांश पेश कर रहे हैं :-

☞ पटना हाईकोर्ट आदेश-केस (CWJc No.-17505/2024)

☞ दिनांक :- 08/08/2025

☞ पीठ :- जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस अशोक कुमार पांडेय

❖ **पृष्ठभूमि**

☞ टेंडर संख्या :- 09/SHSB/Pathology Service/2024-25 (दिनांक-22/08/2024)

☞ उद्देश्य :- बिहार के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाएँ (Hub & Spoke मॉडल)

☞ कुल 7 कंपनियाँ सहभागी

☞ याचिकाकर्ता (Science House + Sodani Hospitals) ने 77.06% छूट की पेशकश की (सबसे अधिक)।

☞ PAC ने इन्हें L7 दिखाकर अयोग्य ठहराया और Respondent 4 & 5 (Hindustan Wellness+Dr. Khanna Pathcare) को L1 घोषित किया (73.05% छूट)।

❖ **याचिकाकर्ता का पक्ष**

☞ Rate कॉलम की समस्या :- पोर्टल पर 'Rate' कॉलम तकनीकी रूप से अनिवार्य था, इसलिए '1' डाला गया। असली वित्तीय बोली Annexure-16 के अनुसार 77.06% छूट थी।

☞ पिछले टेंडरों में '0' या '1' स्वीकार किए गए (राधिका एक्सप्रेस,

यश सर्विसेस, पाटलिपुत्र प्रिंटर्स)।

☞ PAC ने बिना अवसर दिए मनमाना निर्णय लिया।

☞ Respondent 4 & 5 को लाभ पहुँचाने के लिए भेदभाव व पक्षपात किया गया।

☞ इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान और जनहित की हानि होगी।

❖ **प्रतिवादी (राज्य स्वास्थ्य समिति) का पक्ष**

☞ Price Bid Comparison Sheet (ऑटो-जनरेटेड) के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

☞ याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग आंकड़े डाले ('1' और 77.06%), इसलिए अयोग्य घोषित।

☞ Annexure-16 को मात्र indicative format बताया।

❖ **हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ**

☞ इस टेंडर में केवल प्रतिशत छूट (discount) ही मान्य थी, 'Rate' कॉलम अप्रासंगिक था।

☞ PAC ने पहले अन्य टेंडरों में '0' और '1' स्वीकार किया, यहाँ जानबूझकर अलग रवैया अपनाया गया-भेदभाव।

☞ PAC सदस्य श्री राजेश कुमार (Administrative officer) ने Minutes पर हस्ताक्षर नहीं किए-गंभीर संदेह।

☞ Respondent 4 & 5 पात्रता मानदंड (Clause 2.4-20 लाख टेस्ट अनुभव) पूरा नहीं करते थे, फिर भी योग्य घोषित।

☞ सबसे अधिक छूट देने वाले को बाहर कर, कम छूट वाले को अनुबंध देना जनहित के खिलाफ और राज्य को नुकसानदायक।

❖ **न्यायालय का निर्णय**

☞ PAC का 23.10.2024 का निर्णय रद्द।

☞ Respondent 4 & 5 को दिया गया LOI (05/11/2024), Agreement, (19/11/2024) और Letter (31/12/2024) निरस्त।

❖ **राज्य स्वास्थ्य समिति को आदेश**

☞ एक माह के भीतर पुन: निर्णय लें।

☞ मूल्यांकन निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से करें।

☞ अदालत की राय : यह निर्णय मनमाना, पक्षपातपूर्ण और जनहित के

Patna High Court CWJC No.17505 of 2024 dt.08-08-2025
2/62

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.17505 of 2024

1. M/s Science House Medicals Private Limited having its registered Office at 1st Floor, Plot No.- C-65 at Gautam Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, India-462023 through its authorised signatory Mr. Sanchit Chaturvedi, aged about 33 years, son of Satish Chaturvedi, House No.A-07, Ashima Divine City, Near Pebble Bay Phase II, Baghmugaliya, Huzur, PS- Baghsewaniya, Bhopal, Madhya Pradesh- 462043.
2. M/s Sodani Hospitals and Diagnostics Private Limited having its registered office at LG-1, Morya Centre, Opp. Basket Ball Club 16/1, Race Course Road, Indore (M.P) through its authorised signatory Mr. Sanchit Chaturvedi, aged about 33 years, son of Satish Chaturvedi, House No.A-07, Ashima Divine City, Near Pebble Bay Phase II, Baghmugaliya, Huzur, PS-Baghsewaniya, Bhopal, Madhya Pradesh- 462043.
3. Consortium of Science House Medicals Private Limited and Sodani Hospitals and Diagnostics Private Limited having its registered Office at 1st Floor, Plot No.- C-65 at Gautam Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, India-462023 through its authorised signatory Mr. Sanchit Chaturvedi, aged about 33 years, son of Satish Chaturvedi, House No.A-07, Ashima Divine City, Near Pebble Bay Phase II, Baghmugaliya, Huzur, PS- Baghsewaniya, Bhopal, Madhya Pradesh- 462043

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through Additional Chief Secretary, Health Department, Government of Bihar 1st Floor, Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna- 800015.
2. The State Health Society, Bihar through Executive Director, Parivar Kalyan Bhavan, Sheikhpura, Patna.
3. The Executive Director, State Health Society, Bihar, Parivar Kalyan Bhavan, Sheikhpura, Patna.
4. Hindustan Wellness Private Limited, through its director, having its registered office at 107, 1 Floor, Sector-44, Gurugram, Haryana, India, 122001.
5. Dr. Khannas Pathcare Private Limited, through its director, having its registered office at E-8-A, Ground Floor, Hauz Khas, New Delhi, Delhi, India - 110016.
6. POCT Services, having its registered office located at 298-281, Transport Nagar, Kanpur Road, adjacent to Transport Nagar Metro Station, P.S. - Sarojini Nagar, P.O. - Manas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh 226023 through its duly authorized representative, Vinay Mishra, Male aged about 54 years, S/o Late Data Ram Mishra R/o - B-653, P.O. and P.S. - Rajajipuram Lucknow, Uttar Pradesh - 226017.

... ... Respondent/s

WEB COPY

RNI NO.:-BIHHIN/2006/18181
PAN NO.:-AAJFK0065A
DAVP NO.:-129888
GSTIN :- 10AAJFK0065A1Z7
POSTAL Reg. NO.:-PS-35

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
(भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से निबंधित)
ISO 9001 : 2015

www.kewalsach.com www.kewalsachtimes.com www.kewalsachlive.in
प्रधान कार्यालय :- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-14/28, कंकड़बाग, पटना-8000 20 (बिहार)
सम्पर्क संख्या :- 9431073769, 8340360961, 9955077308 ई-मेल :- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

पत्रांक :- 32/kewal sach/2025 दिनांक :- 29/07/25

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार,
पटना।

विषय:- बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दो प्रभावशाली अधिकारियों(BMSICL) के प्रबंध निदेशक श्री निलेश रामचंद्र देवरे और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री सुहर्ष भगत द्वारा बर्बाद करने की सुनियोजित साजिश एवं राजनीतिक षडयंत्र के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य अधिकारों का हनन।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं, एक जागरूक नागरिक एवं पत्रकार होने के नाते, राज्य की जनता एवं लोकतांत्रिक प्रणाली के हित में यह पत्र आपको प्रेषित कर रहा हूँ, ताकि आपको उस खतरनाक साजिश की जानकारी मिल सके जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बेपटरी करने हेतु रची गई है। यह साजिश दो प्रभावशाली अधिकारियों - (1) राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री सुहर्ष भगत (पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के दामाद) एवं (2) बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के प्रबंध निदेशक श्री निलेश रामचंद्र देवरे (पूर्व प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के निजी सचिव) - के बीच गठजोड़ का परिणाम है। इन दोनों अधिकारियों ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को राजनीति का अखाड़ा बनाकर अपने-अपने प्रभावशाली संबंधों का प्रयोग करते हुए नीतिगत प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाया है। श्री सुहर्ष भगत कई वर्षों से राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रमुख पद पर विराजमान हैं और उनके कार्यकाल में - CHO परीक्षा, पैथोलॉजी, एंबुलेंस सेवा, वेंडर चयन जैसी सभी प्रमुख योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएँ सामने आई हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय
बिहार

2025037141 Date :- 31-Jul-2025

सेवा में :-
ACS/Principal Secretary/Secretary
Health Department
Government of Bihar, Patna

विषय :- बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दो प्रभावशाली अधिकारियों (BMSICL) के प्रबंधक निदेशक श्री निलेश रामचंद्र देवर और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री सुहर्ष भगत द्वारा बर्बाद करने की सुनियोजित साजिश एवं राजनीतिक षडयंत्र के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य अधिकारों का हनन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है की मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्र को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है की कृत कारवाई से आवेदक एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के वेबपोर्टल https://dashboard.bihar.gov.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथा संलग्न विवरणी।

विश्वासभाजन
Under Secretary
CM Secretariat, Patna, Bihar

प्रतिलिपि- शशि रंजन सिंह, Darbhanga सदर दरभंगा दरभंगा सदर नगर निगम के पीछे सेनापथ नगर 846004 को सूचनार्थ प्रेषित।

Sl.NO	Sender Name	Address	District	QR Code No
1	शशि रंजन सिंह	Darbhanga सदर दरभंगा दरभंगा सदर नगर निगम के पीछे सेनापथ नगर 846004	Darbhanga	2025037141

Note : This is a computer generated slip.

CM Secretariat
Bihar

मुख्यमंत्री सचिवालय
2025037141

दिनांक :- 29-Jul-2025 जिला :- Patna
नाम :- शशि रंजन सिंह संपर्क सूत्र :- 8210772610

सम्बंधित आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी निम्न प्रकार प्राप्त की जा सकती है :-

1. प्राप्ति रसीद पर अंकित QR Code स्कैन कर।
2. आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर।
3. वेबसाइट https://cmsonline.bihar.gov.in के सर्च विकल्प में बार कोड संख्या दर्ज कर।
4. प्राप्ति रसीद में अंकित बार कोड को मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थापित KIOSK मशीन में स्कैन कर।

नोट :- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति रसीद है। इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

संपर्क सूत्र : 4, देशरत्न मार्ग, पटना, बिहार, पिनकोड : 800001
E: cmbihar@nic.in, P: +91 (612) 2215601, 2217289

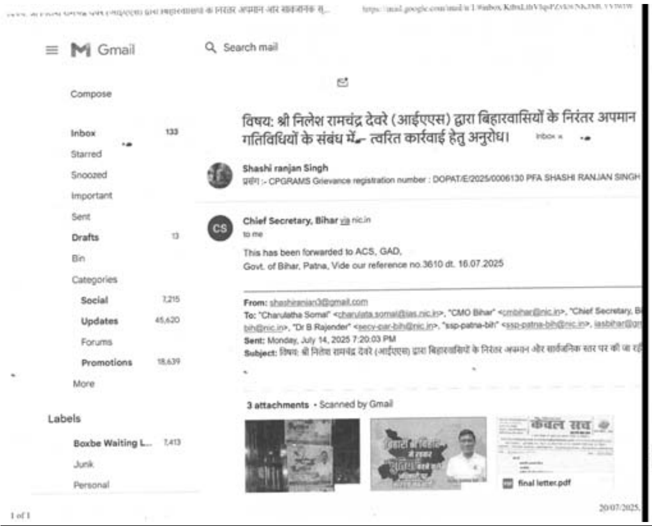

विषय: श्री निलेश रामचंद्र देवरे (आईएएस) द्वारा बिहारवासियों के निरंतर अपमान गतिविधियों के संबंध में - त्वरित कार्रवाई हेतु अनुरोध।

Shashi ranjan Singh
प्रसंग :- CPGRAMS Grievance registration number : DOPAT/E/2025/0006130 PFA SHASHI RANJAN SINGH

Chief Secretary, Bihar via nic.in
to me

This has been forwarded to ACS, GAD,
Govt. of Bihar, Patna, Vide our reference no.3610 dt. 16.07.2025

From: shashiranjan3@gmail.com
To: "Charulatha Somal" <charulata.somal@ias.nic.in>, "CMO Bihar" <cmbihar@nic.in>, "Chief Secretary, B... bih@nic.in>, "Dr B Rajender" <secy-par-bih@nic.in>, "ssp-patna-bih" <ssp-patna-bih@nic.in>, iasbihar@...
Sent: Monday, July 14, 2025 7:20:03 PM
Subject: विषय: श्री निलेश रामचंद्र देवरे (आईएएस) द्वारा बिहारवासियों के निरंतर अपमान और सार्वजनिक स्तर पर की जा रही...

3 attachments • Scanned by Gmail

final letter.pdf

मुख्यमंत्री सचिवालय

2025028783

Date :- 27-Jun-2025

ACS/Principal Secretary/Secretary
Health Department
Government of Bihar, Patna

https://dashboard.bihar.gov.in

Under Secretary
CM Secretariat, Patna, Bihar

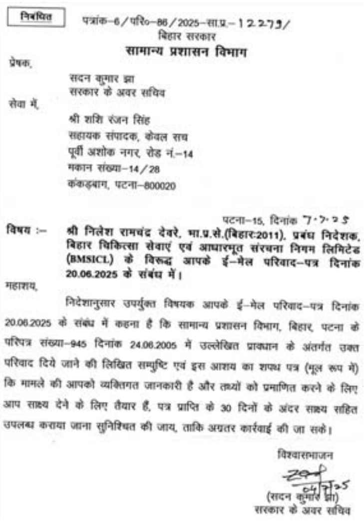

निबंधित

पत्रांक–6/परि०–86/2025–सा.प्र.–12279/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,
सदन कुमार झा
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,
श्री शशि रंजन सिंह
सहायक संपादक, केवल सच
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.–14
मकान संख्या–14/28
कंकड़बाग, पटना–800020

पटना–15, दिनांक 7·7·25

विषय :– श्री निलेश रामचंद्र देवरे, भा.प्र.से.(बिहार:2011), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) के विरूद्ध आपके ई–मेल परिवाद–पत्र दिनांक 20.06.2025 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके ई–मेल परिवाद–पत्र दिनांक 20.06.2025 के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–945 दिनांक 24.06.2005 में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत उक्त परिवाद दिये जाने की लिखित सम्पुष्टि एवं इस आशय का शपथ पत्र (मूल रूप में) कि मामले की आपको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए आप साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं, पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन
(सदन कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

प्रतिकूल था।

❖ **मुख्य कानूनी बिंदु (Supreme Court citations)**

☞ Ramana Dayaram Shetty (1979)-टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता अनिवार्य।

☞ Jagdish Mandal (2007)-मनमाना/पक्षपाती निर्णय होने पर ही न्यायिक हस्तक्षेप।

☞ Reliance Airport Developers (2006)- सार्वजनिक अनुबंधों में निष्पक्षता अनिवार्य।

☞ Afcons Infrastructure (2016)-अप्रासंगिक दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

☞ इस न्यायालय के मत में, प्रतिवादी राज्य स्वास्थ्य समिति और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत द्वारा याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली को अस्वीकार करना अत्यन्त मनमाना है और यह इतना तक है कि प्रतिवादी हिंदुस्तान वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे जनहित के तत्व की पूर्णत: उपेक्षा की गई है। हमारा यह मत है कि इस मामले में प्रतिवादी हिंदुस्तान वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड के संघ को अनुबंध प्रदान करने का निर्णय निष्कपट (बोनाफाइड) निर्णय नहीं है तथा यह जनहित में भी नहीं है। अत: न्यायालय इसे प्रतिवादी, प्रतिवादी राज्य स्वास्थ्य समिति और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत के निर्णय में हस्तक्षेप करने योग्य मामला मानता है और न्यायिक पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

☞ फलस्वरूप, याचिका में संलग्न परिशिष्ट–पी/10 के अंतर्गत पीएसी (PAC) का निर्णय, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली को अस्वीकार कर प्रतिवादी हिंदुस्तान वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड के संघ को कार्य प्रदान किया गया था, उसे निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही, इसके बाद किए गए सभी कार्य जैसे 'एलओआई' (LOI) जारी करना और उक्त संघ के पक्ष में समझौते का निष्पादन भी शून्य और अप्रभावी माने जाएंगे और वे भी निरस्त किए जाते हैं।

☞ प्रतिवादी राज्य स्वास्थ्य समिति और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत को निर्देश दिया जाता है कि वे इस विषय पर आज से एक माह की अवधि के भीतर, उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में एक नया निर्णय लें।

बीएमएसआइसीएल के एमडी के खिलाफ लोकहित याचिका

विधि संवाददाता, जागरण • पटना : बिहार मेडिकल सर्विसेस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) में गंभीर अनियमितताओं और जनविरोधी व्यवहार के आरोपों को लेकर हाई कोर्ट में धीरेंद्र सिंह पासवान ने लोकहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता धीरेंद्र सिंह पासवान ने बीएमएसआइसीएल के एमडी डा. निलेश रामचंद्र देवरे के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारी की कार्यप्रणाली में न सिर्फ वित्तीय अनियमितता और पक्षपात है, बल्कि वे सार्वजनिक स्थानों पर बिहार के लोगों के प्रति अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि बीएमएसआइसीएल में हुई खरीद-फरोख्त और भुगतान के रिकार्ड की स्वतंत्र आडिट कराई जाए और पूरे मामले की जांच या तो न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक स्वतंत्र समिति से कराई जाए।

❖ **निष्कर्ष (Summary Point)**

☞ याचिकाकर्ता की 77.06% छूट वाली बोली को गलत कारणों से खारिज किया गया।

☞ Respondent 4 & 5 को अनुचित लाभ और सरकार को हानि।

☞ हाईकोर्ट ने पूरा अनुबंध रद्द कर दिया और नये सिरे से पारदर्शी मूल्यांकन का आदेश दिया।

जनसुराज ने बिहार के कई विभागों में पहुंच मजबूत की है, इसका नमूना आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल जाएगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार से अलग होने के पहले राज्य में अधिकारियों की पोस्टिंग करते थे इसलिए भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उनकी पैठ मजबूत है और बिहार सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार से संबंधित फाइल निकालने में उनका कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर इसका फायदा उठाकर बिहार के माहौल को खराब करने के प्रयास में लगे हुए है। जनसुराज ने बिहार के विभागों में अपनी पहुंच कितनी मजबूत की है, इसका नमूना आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल जाएगा की जनसुराज नेता के दामाद और पूर्व निजी सचिव को इतना बड़ा पद दे दिया गया है। अब बड़ी-बड़ी बात करने वाले जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, जनसुराज के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह के दामाद और निजी सचिव पर कुछ बोलेंगे। यह कहना उचित नहीं होगा कि सब मिले हुए हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह के माध्यम से जन सुराज ने अपनी पकड़ सभी विभागों में बना ली है और आने वाले दिनों में रामचंद्र प्रसाद सिंह के माध्यम से प्रशांत किशोर और विभागों का खुलासा कर सकते हैं, यह कहना उचित ही होगा।●

निरंतर प्रयास से मिलेगी सफलता : डॉ. योगेश

सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित भाव से कार्य को संपादित करने वाले विभिन्न प्रकार के आपदाओं के बाद भी अपनी समर्पण भाव एवं कर्मठता से उसको पूर्ण करके विराम लेते हैं। आज वर्तमान समय में आरक्षण के सुविधा के बाद भी सफलता उन्हीं के कदम चुनती हैं जिनके अंदर माँ सरस्वती विराजमान हो। महज दो वर्षो के उम्र में जिसके सिर से पिता का हाथ उठ जाता हैं,वह भारत के सर्वोच्च परीक्षाओं में प्रतिभा का लोहा मानवता हो ऐसे होनहार ऊँगली पर गिने जा सकते हैं। जी हाँ; हम बात कर रहे हैं 2017 बैच के मूल रूप से यूपी के बरेली निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ योगेश कुमार सागर की जो खुद्द के साथ साथ अपनी जीवन साथी को भी अपने कंधे से कंधा मिलाकर सफल बनाते हैं। बात उन दिनों की हैं जब डॉ० योगेश बाधाओ को काटते हुए अपने मधुर स्वभाव एवं मिलनसार प्रवृत्ति के साथ उच्चतम योग्यता रखते हुए वर्ष 2015 में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी के रूप में पदस्थापित हुए और सेवा देने शुरू किया इसी संघर्ष के क्रम उनकी विवाह डॉ अवलोकिता अशोक से हुई और उन्होंने पत्नी को चिकित्सा सेवा के साथ-साथ भारत सरकार के सर्वोच्च सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रेरित किया और संघर्ष के दम पर इनकी धर्मपत्नी डॉ अवलोकिता अशोक भी भारतीय राजस्व सेवा के रूप में चयनित हो गई। गौरतलब हो कि आईएएस डॉ० योगेश कुमार सागर के आंखों में जो सपने थे आईएएस बनने की उसके लिए सरकार को सेवा देने के साथ साथ अपने सपनों को पंख लगाने के लिए कड़ी मेहनत की और फलत: 2017 बैच के रूप में सपने साकार हुई। पहले चिकित्सक के रूप में भी डॉ योगेश कुमार सागर जी अपने परिश्रम एवं सेवा भाव को जागृत रखने में कामयाब रहे यही वजह हैं कि डॉ योगेश इसके बाद प्रथम प्रयास में भारतीय राजस्व सेवा और फिर पत्नी को भी अपने साथ साथ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बनवाया और अपने सपने साकार करने में सफल रहे। हमारे पत्रिका प्रतिनिधि **श्रीधर पांडेय** ने 2017 बैच के आईएएस **डॉ० योगेश कुमार सागर**, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के साथ खास मुलाकात की जिसके सम्पादित कुछ अंश:-

❖ **आप किस तरह की परिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं?**

मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी लिपिक थे और माँ गृहिणी हैं ।7 भाई और 4 बहनें में मैं सबसे छोटा हूँ। मैं जब 2 वर्ष के थे तो पिताजी का निधन हो गया था।

❖ **आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई हैं?**

हमारी 12 तक की शिक्षा सरकारी स्कूल से संपन्न हुई। घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा रहा हैं बचपन से ही शिक्षा के प्रति लगाव अच्छा रहा और मैं स्कूल कॉलेज टॉप करता गया। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करते हुए 2006 में सीपीएमटी में सफलता हासिल की जहाँ 8जी रैंक पर था। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से किया।

❖ **चिकित्सा सेवा छोड़कर यूपीएससी की तैयारी का मन कैसे बना लिए?**

मैं एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद दिल्ली में प्राइवेट जॉब में लग गया वही से अपनी सेवा के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए और प्रथम प्रयास में ही 2014 में सिविल सेवा के लिए चयन हुआ और 2015 बैच में मुझे भारतीय राजस्व सेवा मिला। फिर शादी के बाद मैं और

मेरी धर्मपत्नी डॉ अवलोकिता अशोक ने मिलकर तैयारी किया और हम दोनों ने 2016 में एक साथ सफलता हासिल की जहाँ मेरी पत्नी डॉ अवलोकिता अशोक को भारतीय राजस्व सेवा के लिए चयनित हुई और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए बिहार कैडर मिला।

❖ **बतौर आईएएस बिहार सरकार एवं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आपको कैसी लगी?**

बतौर आईएएस मुझे बिहार में कार्य करने का मौका मिला हैं,यहाँ कार्य करने के बहुत स्कोप हैं। सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हैं जहाँ काम करने का बेहतरीन माहौल हैं।

❖ **बिहार में कहाँ कहाँ आपने काम किया हैं और कैसा अनुभव रहा?**

यहाँ मुझे विभिन्न जिलों में कार्य करने का मौका मिला हैं। हर जगह का अपना एक अनुभव रहा है। मैं गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड में बतौर बीडीओ ट्रेनिंग लिया जहाँ कुछ महीने तक कार्य किया और अच्छा अनुभव हैं वहाँ भी काम करने के बहुत सारे स्कोप हैं। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज, डीडीसी बक्सर, नगर आयुक्त भागलपुर, एमडी बुडको के रूप में योगदान दिया उसके बाद निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।

❖ **बतौर आईएएस आपकी क्या प्राथमिकता रही हैं?**

बिहार में कई जगहों पर काम करने का अनुभव रहा और हमारी प्राथमिकता अंतिम पायदान पर खड़े जनता के लिए हैं। उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को ससमय सही ढंग से मिले वह किसी लाभ से वंचित नहीं हो इसपर विशेष फोकस रहता हैं। टीम मैनेजमेंट के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं अन्य सभी तरह की जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से एक लक्ष्य निर्धारण करते हुए ससमय पहुंचाना प्राथमिकता में रही हैं।

❖ **आप युवा हैं और आईएएस भी,आईएएस बनने से पहले मन में प्रशासन के प्रति क्या सोच थी?**

देखिए श्रीधर जी, मुझे प्रशासन से ज्यादा इंट्रेक्शन नहीं था लेकिन मन में एक भ्रांतिया रहती है कि सरकारी काम है तो देर लगेगा, इधर जाइए, उधर जाइए, टाइम किलिंग एवं व्यवहारिक समस्याएं देखने को छिट पुट मिल जाती हैं लेकिन आज के समय में बहुत सी चीजे बदल गई है और बेहतर होती जा रही हैं। ऑनलाइन अपने आवेदन ट्रैक कर सकते हैं, समय निर्धारण अवधि में आपका काम सही है तो वह पूरा हो जाएगा, सहायता केंद्र से कार्यालय में सही कामों का मार्गदर्शन मिलरही हैं। कार्यालय में भी महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए अलग से सुविधाएं मिल रही हैं। प्रशासन में तेजी से सुधार हो रहा हैं साथ ही पब्लिक प्रशासन मैत्रेयी संबंध बेहतरीन स्थापित हो रहे हैं।

❖ **आपने यूपीएससी की तैयारी कैसे की?**

मैंने सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस किया। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया इतना ऐक्टिव नहीं था, जो सेलेक्ट लोग थे उनका इंटरव्यू डीडी 01 पर हमलोग देखते थे साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओ की मैगजीन में भी तैयारी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ देखते थे। सेल्फ स्टडी 8-10 घंटे की निरंतर होती थी। एक लक्ष्य निर्धारित कर रिवीजन नियमित करते थे।

❖ **क्या आप श्योर थे की सिविल सर्विस में आपको सफलता मिलेगी?**

तैयारी अगर सही हो तो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता हैं। एक कॉन्फिडेंस था एमबीबीएस में टॉप करके निकले थे। यूपीएससी में भी प्री, मेंस, इंटरव्यू प्रथम प्रयास में निकलता गया। एक एक स्टेज आत्मविश्वास बढ़ाता गया।

❖ **लबासना की ट्रेनिंग और फील्ड में कार्य अनुभव में क्या अंतर देखते हैं आप?**

दोनों ही बेहद जरूरी होता हैं। लबासना की ट्रेनिंग में हमे थ्योरी सिखाया जाता हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य निष्पादित करना हैं लेकिन फील्ड में अपने स्व विवेक से त्वरित निर्णय लेना होता हैं। उदाहरण स्वरूप फील्ड में जब आप कार्य करते है तो कोई त्योहार है, शांति समिति की बैठक, लॉ एंड ऑर्डर, मैनेजमेंट शांति व्यवस्था सारी चीजे त्वरित निष्पादन करना होता हैं ताकि आम जनमानस में प्रशासन के प्रति विश्वास बरकरार रहे।

❖ **यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे?**

इसमें आपको निरंतर प्रयास करने से सफलता मिलेगी। बेहतरीन गाइड के साथ साथ अपनी आत्मंथन जरूर करे कि कहाँ कमियाँ है, क्या समस्याएं आ रही है उसको दूर करें। प्रैक्टिस रिवीजन करते रहे है। अभी आप इसबार के टॉपर की ही देख लीजिए 6जी प्रयास में टॉपर बनी है जो निरंतर प्रयास का परिणाम हैं। हर प्रतियोगी युवाओ का सपना सिविल सर्विस होता है जिसमे लोग प्वाइंट में सफल होते है तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं हैं। यूपीएससी की बेहतरीन तैयारी आपको एक बेहतर इंसान बना देती है भले ही आप कुछ अंक से चूक गए हो आप दूसरे क्षेत्र में भी अनुशासन प्रिय कार्य करते हुए समाज को, राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं।

शिक्षक का अश्लील वीडियो वायरल

सरपंच-पंच संघ ने एसडीपीओ राघव दयाल को दिया ज्ञापन

● अमित कुमार

जयनगर के एक शिक्षक का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला दिन पर दिन गहराता चला जा रहा है। बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कोचिंग शिक्षक को छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा जा सकता है। यूं तो शिक्षा के मंदिर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन यहां अगर ऐसी घटनाएं होने लगें, तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती है। बता दें कि मधुबनी के कोचिंग संस्थान से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह जयनगर के भेलवा चौक गली स्थित 'मैथमेटिक्स' नामक कोचिंग संस्थान से जुड़ा है। इस संस्थान के संस्थापक और शिक्षक का नाम राकेश बताया जाता है।

विदित हो कि पीड़िता के बयान पर थाने में शिक्षक समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने बताया है कि वह राकेश कुमार यादव नामक शिक्षक के कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करती थी। आरोप है कि कोचिंग में अकेला पाकर टीचर छेड़खानी किया करता था। पीड़िता ने घटना को लेकर किसी को जानकारी नहीं दी थी। आरोप यह भी है कि कोचिंग संस्थान के मकान-मालिक कुलदीप सिंह व कमलाबाड़ी निवासी सोनू चौधरी भी पीड़िता के साथ छेड़खानी करते थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों ने उससे कहा कि शिक्षक का वीडियो बनाओ, 20 लाख रुपये वसूलना है। करीब बीस दिन पहले कोचिंग में आई तो घर जाने के क्रम में मकान मालिक कुलदीप सिंह व सोनू चौधरी ने मुझे पकड़ लिया। पीड़िता ने आगे कहा कि आरोपियों ने मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी और कहा कि शिक्षक का आज तुम वीडियो बनाओ नहीं तो जान से मार देंगे। इसके बाद मैंने रूम में जाकर मोबाइल का वीडियो खोल दिया। इसी क्रम में शिक्षक आया और मुझे पकड़ कर अश्लील हरकत करने लगा।

नजर पड़ने पर शिक्षक मोबाइल को छीनने की कोशिश करने लगा। इस दौरान कुलदीप सिंह और सोनू चौधरी ने मेरे मोबाइल से वीडियो अपने फोन में ले लिया और मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी कुलदीप सिंह और सोनू चौधरी ने उसे फोन करके बोला कि जयनगर आओ नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे। पीड़िता ने कहा कि मैं डर से अपनी बहन के घर नेपाल चली गई। इसी बीच कुलदीप सिंह और सोनू चौधरी ने मेरा वीडियो वायरल कर दिया। इधर, स्थानीय पुलिस ने शिक्षक राकेश कुमार यादव, मकान मालिक कुलदीप सिंह, सोनू चौधरी के अलावा वीडियो को वायरल करने वाले इंटरनेट मीडिया संचालक समेत अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।

बहरहाल, जयनगर में शिक्षक का अश्लील वीडियो वायरल मामले को लेकर प्रखंड सरपंच-पंच संघ की बैठक आयोजित हुई। सरपंच-पंच संघ जयनगर ने जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीपीओ राघव दयाल को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार व सचिव मोहम्मद जहाँगीर हाशमी के नेतृत्व में पहुँचे शिष्टमंडल ने कहा कि यह वीडियो समाज व शिक्षा के वातावरण को दूषित कर रहा है। वही संघ के सदस्यों का कहना था कि इस प्रकार की घटना निंदनीय है। बैठक में शिक्षक का अश्लील वीडियो वायरल से समाज को दूषित करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें जयनगर के एक शिक्षक वीडियो वायरल की घटना पर निंदा करते हुए कहा की सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से विभिन्न प्लेटफॉर्मो पर शेयर कर समाज को दूषित किया जा रहा है। वीडियो को ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।●

एसडीपीओ राघव ने किया थाने का औचक निरीक्षण

स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन कर जवानों को दिए शुभकामनाएँ व संदेश

● अमित कुमार

मृदुभाषी एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के तौरपर पहचान रखने वाले राघव दयाल इन दिनों नेपाल से सटे मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी के पद पर कार्यरत्त हैं। विदित हो कि बीते जून माह माह में ही उनका तबादला पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, जमुई से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर के पद पर किया गया। कानून और विधि व्यवस्था पर सख्ती से काम को लेकर जाने जानेवाले राघव पद ग्रहण करते ही स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था सर्वोपरि होगी, शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन होगा, ट्रैफिक समस्या का समाधान प्राथमिकता में रहेगा एवं आम जनता को सुरक्षा का भरोसा देना ही मुख्य उद्देश्य है।

गौरतलब है कि कर्तव्यपरायणता को अपना धर्म समझने वाले एसडीपीओ राघव दयाल ने बीते दिनों बासोपट्टी थाना में समीक्षा बैठक की। बता दें कि इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर दिए कई सख्त निर्देश भी उन्होंने दिये। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बासोपट्टी थाना की औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान थाना के लंबित कांडों की स्थिति, शराबबंदी, महिला उत्पीड़न और अपराध नियंत्रण से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। एसडीपीओ राघव दयाल ने सभी पदाधिकारी को लंबित मामले का शीघ्र निष्पादन, गस्ती करने एवं शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही एसडीपीओ ने थाना परिसर में साफ सफाई अभिलेखों के रख-रखाव एवं जनता से संवाद की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी निर्देश दिया।

बताते चले कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसडीपीओ राघव दयाल ने अपने सहकर्मियों के बीच झंडोतोलन किया तथा शीष झुकाकर तिरंगे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। उक्त मौके पर राघव दयाल ने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और अपने कार्यों में ईमानदारी रखने की बात कही। साथ ही अनुमंडल की समस्त जनता समेत वरीय पदाधिकारियों, सभी थानाध्यक्षों व पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी।●

ऑटिज्म सेंटर एमपथी माइंड का पटना में शुभारंभ

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

ऑटिज्म सेंटर का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के करकमलों से 7 अगस्त 2025 को शेखपुरा पटना में किया गया। ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनी अत्याधुनिक 'एमपैथी माइंड' ऑटिज्म सेंटर का शुभारंभ गुरुवार को शेखपुरा, पटना में हुआ। उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। मंत्री श्रवण कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "ऑटिज्म और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां अब भी समाज में जागरूकता के अभाव के कारण नजरअंदाज हो जाती हैं। 'एमपैथी माइंड' जैसे केंद्र न केवल बच्चों को बेहतर इलाज और थेरेपी देंगे, बल्कि उनके परिवारों को भी सही दिशा और सहयोग प्रदान करेंगे। सरकार चाहती है कि ऐसी संस्थाएं हर जिले में स्थापित हों, ताकि लोगों को दूर-दराज जाने की जरूरत न पड़े।" संस्था की संस्थापक एवं मनोचिकित्सक डॉ. सुप्रिया कुमारी ने बताया कि यह सेंटर विशेष रूप से ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए समर्पित है। यहां स्पीच थेरेपी,

सेंसरी थेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी समेत कई आधुनिक तकनीकों से इलाज किया जाएगा। डॉ. सुप्रिया ने कहा कि अब ऐसे मामलों के इलाज के लिए दिल्ली या रांची जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां स्थैड नई दिल्ली की अनुभवी डॉक्टरों सहित विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध है। सेंटर पर ऑटिज्म, एडीएचडी, देर से बोलना, हकलाना, पढ़ाई में कमजोरी, व्यवहारिक बदलाव, मिर्गी, सिरदर्द और तनाव जैसी समस्याओं का भी थेरेपी और परामर्श से इलाज होगा। इस संस्था के संस्थापक डॉ सुप्रिया कुमारी मनोचिकित्सक ने अत्याधुनिक ऑटिज्म सेंटर एमपैथी माइंड शेखपुरा पटना में विभिन्न थिरैपियो द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार रुप से चर्चा की। यह सेंटर विशेष रूप से ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए समर्पित हैं। जहां आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञों की टीम द्वारा बच्चों के मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास पर कार्य किया जाता है। यहां स्पीच थेरेपी सेंसरी थेरेपी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ऑक्युपेशनल थेरेपी बिहेवियर थेरेपी जैसे तमाम अत्याधुनिक तकनीकों से चिकित्सकों की टीम द्वारा यहां सफल एवं सुलभ ईलाज किया जाता है। अब मनोरोग से संबंधित विभिन्न बीमारियों के ईलाज हेतु रांची और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है शेखपुरा पटना में ही अब अपनी सेवा दे चुकी है स्थैड नई दिल्ली की डॉक्टर उपलब्ध हैं अगर बच्चों में ऑटिज्म ADHD कमजोर बुद्धि, देर से बोलना, हकलाना, तनाव, पढ़ाई में कमजोर, व्यवहार परिवर्तन, जिद्दीपन, मिर्गी, बार बार बेहोश होना, सिर दर्द, इत्यादि रोगों से ग्रसित है। इन रोगों का विभिन्न थेरेपी द्वारा चिकित्सक के परामर्श से सफल ईलाज होता है। कार्यक्रम में डॉ. अखिल पीयूष (पूर्व रेसिडेंट, एम्स नई दिल्ली), डॉ. (प्रो.) अमरदीप कुमार (निदेशक माइंड हॉस्पिटल पटना), डॉ. अनंत कुमार वर्मा (विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा, पावापुरी नालंदा), विपिन कुमार (निदेशक, गोल इंस्टीच्यूट पटना) और डॉ. पी. कुमार (कैंसर सर्जन) समेत हजारों लोग मौजूद रहे।●

वांछित शूटर गौतम उर्फ चीनी गिरफ्तार

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

बहुत सारे मामलों में फरार चल रहे अपराधी गौतम कुमार उर्फ चीनी, पिता–जनक देव यादव उर्फ मनक देव यादव, मरांची थाना, पुनपुन निवासी को मसौढ़ी पुलिस ने अनुमंडल कार्यालय के पास से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह मुकेश उर्फ छोटन, पिता–जगदीश प्रसाद के हत्याकांड में सरेंडर करने गया था। लेकिन पर्याप्त दस्तावेज की कमी के कारण उस दिन सरेंडर नहीं हो सका। पुलिस ने उसे लौटते वक्त दबोच लिया था। इस पूरे मामले में एएसपी कोमल मीणा ने प्रेस कांफ्रेस आयोजित करते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधी गौतम उर्फ चीनी धनरूआ थाना कांड संख्या-118/25, दिनांक-18/02/2025 के कांडों में और रामकृष्ण नगर थाना कांड संख्या 653/25 दिनांक 10/08/2025 को गोलीबारी करने और शराब एक्ट मामले में यह फरार चल रहा था। इसके अलावा दूसरे थानों में हत्या का प्रयास, हत्या, गोलीबारी करने और मद्य निषेध एक्ट में सहित कई मामले में संलिप्त रहा है। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसे जुवेनाइल में भेजा जा रहा है। इसके अलावा उस केस में अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। इस दौरान बताया गया कि बीते चार माह पूर्व मसौढ़ी थाना कांड संख्या–298/25 के तहत अशोक प्रसाद, पिता–सुरुढ़ी प्रसाद, पूरनचक के द्वारा अज्ञात पर हुए प्राथमिकी पर पुलिस अनुसंधान में जुटी है।●

धूमधाम से मनाया गया 79वाँ स्वतंत्रता दिवस

अनुमंडल कार्यालय मसौढ़ी में एसडीओ अभिषेक कुमार, एसडीपीओ कार्यालय में एसपी कोमल मीणा, अधिवक्ता संघ में महासचिव राकेश कुमार, मसौढ़ी सिविल कोर्ट में एडीजे-2 संजीव कुमार, मसौढ़ी उपकारा में उपकार सुपरिडेंटेंट विपिन कुमार, मसौढ़ी थाना में अनिल कुमार, पीपीएस स्कूल में प्राचार्य सुभाष चन्द्र के अलावा सुशीला सुजाता बीएड कॉलेज आशुतोष कुमार, धनरूआ थाना में शुभेन्दु कुमार, कादिरगंज थाना में पूनम कुमारी ने झंडा फहराया। मसौढ़ी, गांधी मैदान में मुख्य समारोह में विधायक रेखा देवी ने झण्डोतोलन किया। ● **रिपोर्ट :-श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव**

ओल्ड फ्रेंड्स क्लब मसौढ़ी ने जीता फुटबॉल मैच

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

स्व० रामाश्रय प्रसाद गुप्त मेमोरियल फाइनल फुटबॉल मैच का 47वां आयोजन मसौढ़ी के गांधी मैदान में किया गया। इस मैच का उद्घाटन मसौढ़ी विधायक रेखा देवी, फुलवारी शरीफ पटना के विधायक गोपाल रविदास और पूर्व सदस्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग निहोरा प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से किया। मैच बेहद रोमांचक रहा। पहले हाफ में ताज क्लब पटना ने एक गोल कर बढ़त बनायी, दूसरे हाफ में ओल्ड फ्रेंड्स क्लब ने शानदार तीन गोल का प्रदर्शन करते हुए लगातार तीन गोल दाग दिया। इसके जवाब में ताज क्लब पटना एक ही गोल कर सका। अंतत: ओल्ड फ्रेंड्स क्लब मसौढ़ी ने

यह मुकाबला जीत लिया। विजेता खिलाड़ियों को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन शिक्षक पंकज कुमार और विजय गुप्ता प्रेस ने संयुक्त रूप से किया। इसकी अध्यक्षता शिक्षाविद् राहुल चंद्रा ने किया। इस कार्यक्रम में ओल्ड फ्रेंड्स क्लब के महासचिव मुकुल कुमार, संयुक्त सचिव एवं कोच इम्तियाज अहमद, खुशबू रानी (जदयू नेत्री), रंजु यादव (सामाजिक कार्यकर्ता, मसौढ़ी), डॉ० नागेशर (होम्योपैथिक), विजय कुमार (जिला परिषद् प्रतिनिधि) ने शिरकत की।●

भाजपा के विधायक, सांसद फंड का लोभ छोड़ें

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा का समाज में काफी प्रतिष्ठा है, आज भी लोग कलयुग के सत्य हरिश्चंद्र मानते हैं। आज भी लोगों में पूर्ण विश्वास है कि भाजपा के विधायक, सासंद नहीं फंड लेते होगें, नहीं कमीशन लेते होगें। जनता में बना विश्वास को कायम रखने के लिए विधायक, सासंद फंड लेना छोड़ दें? फंड छोड़ देने से कमीशन भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कमीशन का मतलब, सरकार द्वारा मिला फंड मे बटवारा करना, बंटवारा के मतलब गुणवत्ता गायब। कमीशन के कारण ही निर्माण कार्य के समय ही पुल, भवन , स्कूल भवन का छत टुकड़े टुकड़े गिर जाता है जिससे छात्र का सिर फट जाता है, कितना बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसका जिम्मेदार फंड देने वाले ही होगें।●

हथियार का मुकाबला लाठी से संभालेंगे सिपाही

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

सिपाही अब हथियारों हथियारों की जगह लाठी का इस्तेमाल करेंगे। हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस अभियान और प्रशिक्षण के दौरान ही होगा। इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने नई नीति तैयार की है। इस नीति के तहत बिहार पुलिस मुख्यालय विभिन्न जिला और इकाइयों को भारी मात्रा में बीपी हेलमेट, पॉलीकार्बोनेट ,लाठी, फील्ड और बॉडी प्रोडक्ट खरीद कर उपलब्ध करा रहा है। हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस अभियान और प्रशिक्षण के दौरान होगा। जरूरत पड़ने पर ही हथियार के इस्तेमाल की बिहार पुलिस की है नई नीति। हेलमेट पॉलीकार्बोनेट लाठी, शील्ड और बॉडी प्रोटेक्टर की हो रही है खरीद। डायल 112 राइफल की जगह पिस्टल विशेष इकाइयों को ऑटोमेटिक गण प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं को उपलब्ध

कराए गए हथियार और गोला बारूद।

अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ कुमार ने बताया की नई नीति को लेकर पुलिसकर्मियों को बड़े हथियार की जगह छोटे और हल्की हथियार दिए जा रहे हैं, वर्तमान में श्री नोट श्री राइफल को फेज आउट करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को उनकी जगह एसएलआर 7,62 एफएम राइफल उपलब्ध कराई जा चुकी है। श्री नाट श्री में हर फायर के बाद कारतूस बदलना पड़ता है जबकि एसएलआर एक बार नहीं 20 राउंड फायरिंग की सुविधा होती है। इसके साथ ही विशेष इकाइयों को ऑटोमेटिक गण दिए जा रहे हैं। जो लगातार फायर करने में सक्षम है वहीं डायल 112 के इमरजेंसी रिस्पांस 92 में तैनात पुलिस कर्मियों को राइफल की जगह पिस्टल दी गई है। हल्की और आधुनिक उपकरण मिलने से पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी।

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि लाठी डंडे वाले पुलिस के हाथ में देख कर अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। इसके बारे सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। अनयथा पुलिस असुरक्षित हो सकती है। आज समुचे बिहार अपराध के नगरी बन चुकी है ऐसे में पुलिस को हथियार विहीन कर देना पुलिस के सेहत के लिए ठीक नहीं है।●

रुपा देवी ने बदल डाली फतुहा की सूरत

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

फतुहा के मुख्य पार्षद रुपा देवी ने फतुहा का सुरत बद दिया, सुरत बदलने में उप मुख्य पार्षद अंजनी कुमारी का सहयोग रहा। सबसे बड़ा सहयोग एवं श्रेय फतुहा के निवासी आ था। फतुहा कुल वोटर लगभग 22000 हजार था, जिसमें 22000 हजार लोगों ने रुपा बेटी को वोट का तोहफा दिया। रुपा बेटी ने सचमुच में फतुहा का सुरत बदल दिया। बाहर से आई महिला उस समय भारी मुसीबत में फंस जाती थी जब शौचालय कि जरूरत होती थी। रुपा बेटी ने इस समस्या को दुर कर दी। चार शौचालय कार्यरत हैं और प्रक्रिया में लगा हुआ है। आवश्यकता के अनुसार पानी का टकीं का व्यस्था कर दिया। समुचे फतुहा में कैमरा, गली नाली, सभी जगह बिजली की वयवस्था कर दी गई। नगर परिषद के वार्ड संख्या- 15 नोहटा में और 27 के कॉपरेटिव कॉलोनी में मिट्टी भराई, चहारदीवारी, फुटपाथ, पेभर ब्लॉक, पार्क निर्माण का शिलान्यास नगर परिषद की मुख्य पार्षद रूपा कुमारी एवं उपमुख्य पर्षद अंजनी कुमारी ने फीता काटकर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह समाजसेवी टुनटुन यादव, उपमुख्य

पार्षद प्रतिनिधि बबन यादव, समाजसेवी सुधीर कुमार यादव, पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोप, दयानंद यादव, अनिल कुमार उर्फ कारू के अलावा पार्षद अजीत कुमार, पूनम देवी, दीपक कुमार, हैवी यादव, सोनी बेटी, शीला पटेल, राकेश कुमार, ममता पटेल, सुरेंदर यादव, संजीव कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार, अनिल कुमार, डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल मौजूद रहे। आयोजक राहुल कुमार ने बताया कि नगर परिषद की जनता की मांग पूरी होने जा रही है।

नगर परिषद में पार्क और फुटपाथ की कमी थी। इसका शिलान्यास हो जाने से यहां की जनता में हर्ष है। इसका निर्माण कर जल्द ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वही लोगों ने रूपा कुमारी जिन्दाबाद, टुनटुन यादव जिन्दाबाद का नारा से आसमान गुंज उठा।●

चूना है 70 बीमारियों की दवा

भाजपा कार्यालय में स्वास्थ्य शीविर का आयोजन

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

भाजपा कार्यालय मां तारा उत्सव पैलेस गोविंदपुर फतुहा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसका अध्यक्षता भाजपा नगर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि चुना कई बीमारियों के लिए अमृत है। चुना का एक टुकड़ा मिट्टी के बर्तन में डालकर पानी से भर दें। चूना गल कर नीचे बैठ जाएगा तथा पानी ऊपर होगा। वही एक चम्मच पानी किसी भी खाने की वस्तु के साथ लेना है। 50 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी कैल्शियम की दवा शरीर में जल्दी नहीं घुलती है परंतु चुना तुरंत घुल जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है जैसे किसी को जौंडिस हो जाने पर सबसे अच्छी दवा है गेहूं के दाने के बराबर चूना गने का रस में मिलाकर लेने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।

चुनाव नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता उसकी अगर गन्ना का रस के साथ चुना पिलाया जाए तो डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लग जाएगा और जिन महिलाओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उनकी बहुत अच्छी दवा है। यह चुना पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए बहुत अच्छी दवा है। इससे यादाशत काफी बढ़ जाती है, यह लंबाई भी बढ़ाती है। मंदबुद्धि के बच्चों के लिए सबसे बेहतर दवा है जो बच्चे के दिमाग कमजोर है। महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित सभी बीमारियों के लिए सबसे बेहतर दवा है। गेहूं के दाना के बराबर चूना खाना चाहिए। दाल में या लस्सी में मिलाकर नहीं तो पानी में घोल के पीना चाहिए। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चुनाव रोज खाना चाहिए। क्योंकि गर्भवती मां को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और चुनाव कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है।गर्भवती मां को चुना खिलाना चाहिए, अनार के रस एक कप और चुना गेहूं के दाने के बराबर मिला कर रोज खिलाएं। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो चार फायदे होंगे। पहले मां को बच्चों के जन्म के समय कोई कष्ट नहीं होगी तथा नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा बच्चा जो पैदा होगा वह बहुत ही हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा जिसकी मां ने चुना खाया है। चौथा बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत तेज होता है।

डॉक्टर कहेंगे कि घुटना घिस गया है घुटना बदलना होगा। चुना लेने से घुटना बदलना नहीं पड़ेगा। कोई भी दवा चिकित्सक के सलाह से इस्तेमाल करें। इस अवसर पर रेखा शर्मा, सीमा कुमारी, पूजा कुमारी, अनिल सिंह, सुनील सिंह, पुनम पटेल, कुसुम पटेल, आरती पटेल, निशांत,शोभा पटेल, मिल्ली पटेल, ममता पटेल आदि शामिल हुए।●

सरकारी स्कूल निर्माण में कमीशन का कमाल

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

सरकारी स्कूलों एवं सरकारी भवन या पुल अक्सर क्यों ढ़ह जाते हैं जबकि अंग्रेजो के समय का बना पुल सैकड़ो साल तक नहीं टुटा जब तक कि उसे ढाहा नहीं जाए दूसरी तरफ विगत् 15-20 वर्षो के अंदर बनने वाले स्कूल और सरकारी स्कूल या भावनाओं की स्थिति तुरंत जर्जर हो जाती है ऐसा क्यों दरअसल जब से ठेकेदारी प्रथा आरंभ हुई है तब से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खत्म हो गई है। निर्माण पर खर्च किए जाने वाली राशि का अधिकांश हिस्सा ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच कमीशन के तौर पर बंदर बांट हो जाता है। जब तक ठेकेदारी प्रथा से काम होगा तब तक काम की गुणवत्ता में सुधार सभंव नहीं है। इस संदर्भ में सत्ता पक्ष के छोटे से बड़े विधायक हो या सांसद कोई चर्चा तक करना नहीं चाहता है।

☞ **मसौढ़ी में स्कूल के छत से गिरा पलास्टर बाल बाल बचे बच्चे :-** मसौढ़ी प्रखंड के सुपहुली स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। पढ़ाई के दौरान अचानक छत का बड़ा हिस्सा कक्षा 6 का बड़ा हिस्सा गिर गया। गलीमत है कि छत गिरने के समय नहीं था छात्र नहीं था। घायल नहीं हो सका क्लास रूप में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा था इस दौरान छत का एक बड़ा दो बच्चों के सीट पर गिरा। संजू बस उसे वक्त वहां पर बच्चे नहीं थे। संयोग वश उस समय बच्चे नहीं था। बड़ी हादसे टल गया। मोहन चक प्राथमिक विद्यालय के छत से गिर रहा प्लास्टर। विक्रम मोहनचक गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की स्थिति जर्जर है। छत दरक चुकी है और प्लास्टिक गिर रहे हैं शिक्षक और छात्र भय के माहौल में पढ़ाई करने का विवश है। वर्तमान में विद्यालय में 55 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

मनेर के शेरपुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रामपुर का भवन अत्यंत जर्डन स्थिति में है विद्यालय की चार दिवारी के अंदर तालाब का दृश्य है जबकि स्कूल का निर्माण अतिक्रमण के कारण रुका हुआ है। छत टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा है शिक्षक और छात्र दोनों भयभीत है।●